

[Dr. R. K. Chakrabarty] This is not the way to improve the condition of the country. We will have to have something concrete and take care of this population factor and the foodgrains factor. Also the total trade in foodgrains in the whole country must be taken under Government control and the people, especially the rural people, must be assured of a minimum quantum of foodgrains every week, every month, throughout the year.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stand* adjourned till 2.00 P.M.

The House then adjourned for lunch at fifty-eight minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock, The Vice-Chairman, Shri V. B. Raju, in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN: Shri Indta-deep Sinha.

REFERENCE TO SITUATION IN KURUKSHETRA

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं सरकार का ध्यान एक तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। एक बजे के करीब जब मैं आ रहा था तो मुझे सूचना दी गई कि कल कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री जयप्रकाश जी की एक आम सभा है। लेकिन श्री बंसी लाल की सरकार ने वहाँ पर तमाम पुलिस भेज दी है। *Interruption* सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सब स्थानों पर पुलिस तैनात कर दी गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस सरकार को कहें और यह सरकार इस बात की व्यवस्था करे कि वहाँ पर कोई अणु-डैमोक्रेटिक काम न हो। *Interruption*। हमने श्री रणवीर सिंह से कहा कि आप श्री बंसी लाल को फॉन करों कि श्री जय प्रकाश जी की मीटिंग टूटने के प्रकार से है। वहाँ पर स्थिति यह है कि सब लाउडस्पीकर बन्द कर दिए गये हैं, धारा 144 लागू कर दी गई है और सभी कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया

गया है। हमारे पोस्टरों को फाड़ दिया गया है... (*Interruption*) यह सब क्यों हो रहा है? इस प्रकार से श्री बंसी लाल की सरकार नहीं चल सकती है।

श्री रणवीर सिंह (हरियाणा) : अभी वहाँ पर एंगेम्बली का गैरान हो रहा है।

श्री राजनारायण : वहाँ पर हजारों कार्यकर्त्ता बन्द कर दिये गये हैं।

उप सभाध्यक्ष (श्री वी. बी. राजू) : श्री राजनारायण जी, अब आप बँट जाइयें।

DISCUSSION UNDER RULE 176 DISCUSSION RE. WIDESPREAD SCARCITY AND FAMINE CONDITIONS IN SEVERAL PARTS OF THE COUNTRY— CONTD

श्री इन्द्रदीप सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज देश के अनेक भाग में अभाव, अकाल और सूखे की स्थिति है। वह बड़ी गम्भीर है। अखबारों में प्रकाशित होने वाले तथ्यों का एकत्रित करके देखा जाय तो पता चलता है कि हमारे देश के आधा दर्जन से अधिक राज्यों में आज अत्यन्त शोचनीय स्थिति फैली हुई है। आसाम के स्वातपाड़ा जिले में 92 फीरदों से अधिक लोग अकाल से प्रभावित हैं और वहाँ पर अखबारों में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार तीन लाख से अधिक लोग घास और पत्तों खाकर जी रहे हैं। गुजरात के 18,000 में से . . .

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal): Where is the senior Minister. Mr. Jagjivan Ram.'

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P SHINDE): He is coming.

श्री इन्द्रदीप सिंह : गुजरात के कुल 18,000 गांवों में से 13,000 गांव प्रभावित हैं। पड़ोसी राज्य हरियाणा में 2 जिलों में अभाव की स्थिति है—महेंद्रगढ़ और भिवानी में—और अखबारी रिपोर्टों के अनुसार लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश में काफी बड़ा हिस्सा अभाव से पीड़ित है। उड़ीसा में, जो अखबारों

में समाचार निकलें हैं, उनसे मालूम होता है कि इस शताब्दी का सबसे भयंकर अकाल और अभाव फैला हुआ है और 2478 ग्राम पंचायतों को उड़ोसा संस्कार ने अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। राजस्थान में लगभग 2 करोड़ जनसंख्या प्रभावित है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले प्रभावित हैं और पश्चिम बंगाल में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ से ज्यादा लोग, वहाँ को लगभग एक-चौथाई जनसंख्या, प्रभावित है। इस प्रकार, महाद्वय, देश के अनेक हिस्सों में, आधे दर्जन से अधिक राज्यों में, अभाव की स्थिति है, और यद्यपि सरकार की ओर से बराबर इसका खण्डन किया गया है लेकिन अखबारों में खबरें आती रहती हैं कि कुछ लोगों की भूख से मृत्यु भी हो गई है। मौने पढ़ा है, कृषि मंत्री ने यहाँ पर भी, लॉक सभा में, इस बात का खंडन किया है और कहा है कि सरकार की ओर से पता लगाया गया और ये खबरें निराधार पायी गईं। निराधार खबरें भी अक्सर उड़ायी जाती हैं, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि जब भी भूख से मौत की खबरें आती हैं और सरकार को और से जांच की जाती है तो जांच-रिपोर्ट में आता है कि वह व्यक्ति कमजोरी के कारण नर गया, कौ-दस्त होने के कारण मर गया। इस प्रकार की खबरें आम तौर से जो सरकारी रिपोर्टें आती हैं उनसे मिलती हैं। जो भी हो, वह मृत्यु, भूख और अभाव से हुआ कटूती है क्योंकि अभाव या अकाल काँड़ सांप नहीं है कि आकर एक दिन काट लेता है। धीरे धीरे शरीर की शक्ति समाप्त हो जाती है और एक दिन वह व्यक्ति मर जाता है और मरने के समय उसे काँड़ न काँड़ बीमारी हो जाती है। लेकिन अगर निष्पक्षतापूर्वक इन तथ्यों पर विचार किया जाए तो हमें मानना पड़ेगा कि ये अभाव और अकाल की मौतें हैं और इस प्रकार की मौतें हो रही हैं यह काफी चिंता की बात है।

उपसभाध्यक्ष महाद्वय, यह स्थिति हमारे देश में दुर्भाग्यवश अक्सर पैदा हो जाता करती है और इनके पीछे कई तथ्य हैं, कुछ मानवीय हैं, कुछ दैवी हैं। मैं दैवी तथ्यों की ओर इशारा नहीं करूँगा क्योंकि पिछले वर्ष भी

और इस वर्ष भी हम बराबर इस पर चर्चा कर चुके हैं—कहीं बाढ़ आ जाती है कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं वर्षा का अभाव हो जाता है और इन कारणों से अभाव या अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। तो हर साल कुछ न कुछ इलाका बाढ़ या सूखे से पीड़ित रहता है। दुर्भाग्यवश, अभी हमारा देश या उसकी सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि कह सके कि हमने बाढ़ और सूखे से बचाव की गारण्टी कर ली है। गारण्टी करने की स्थिति में हम नहीं हैं। तो बाढ़ और सूखे के रहते हुए भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस प्रकार की दुस्सह परिस्थिति देश के किसी हिस्से में पैदा नहीं हो। उसके लिए प्रथम आवश्यकता इस बात की है कि खेती की पैदावार ऐसी हो, खास कर अनाज की पैदावार ऐसी हो, कि कहीं इस प्रकार की अभाव की स्थिति पैदा न हो। कुछ दिनों पहले अग्रिकल्चरल प्राइसिंग कमीशन ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि चौथी पांच-साला योजना में जो 11 करोड़ 40 लाख टन, यानी 114 मिलियन टन खाद्यान्न की पैदावार का लक्ष्य रखा गया था, वह प्राप्त नहीं हुआ है। और 1973-74 में कितनी पैदावार हुई इस बारे में सरकारी तौर पर आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं, लेकिन अनुमान यह है कि 104 या 105 मिलियन टन से ज्यादा अनाज पैदा नहीं हुआ है। हमारे देश में जन संख्या हर साल बढ़ती जाती है और अगर अनाज की पैदावार में वृद्धि नहीं होती है तो इसके कारण देश में अनाज की कमी हो जाती है। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी कमी हो जाने से इस तरह की स्थिति पैदा हो जाय कि कुछ लोगों को खाने को न मिले, कुछ लोग भूख से मर जायें, भीख मांगने के लिये मजबूर हो जायें, यह आवश्यक नहीं है। यह स्थिति इस कारण पैदा हो गई है कि देश में तो भी अन्न पैदा होता है जिसका संग्रह और वितरण सरकार को अच्छी तरह से करना चाहिये, वह सरकार ने नहीं किया है।

उपसभाध्यक्ष महाद्वय, एक साल पहिले सरकार ने गहूँ का थोक व्यापार अपने हाथ में लिया था। उस समय यहाँ पर हमारे मित्र बैठे नहीं हैं, अनेक दलों के मित्र हैं, उन लोगों ने बहुत शोम्गुल मचाया था, हंगामा किया

[श्री इन्द्रदीप सिंह]

था कि सरकार ने गेहूँ का थोक व्यापार अपने हाथों में ले लिया है और यही कारण है कि सरकार को अनाज नहीं मिला तथा बाजार में गायब हो गया और कीमतें बढ़ गईं। मैं समझता हूँ कि इन्हीं लोगों के शोरगुल की वजह से सरकार धबका गई और उसने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इस साल गेहूँ का थोक व्यापार बड़े बड़े व्यापारियों के जिम्मे सौंप दिया। इन व्यापारियों ने सरकार को विश्वास दिलवाया था कि हम इस साल आप को 50 लाख टन गेहूँ दे देंगे। उसने इस बारे में जो एजेंट मقرر किये उन्होंने यह आश्वासन दिलाया कि इससे भी ज्यादा गेहूँ सरकार को दे दिया जायेगा। सरकार ने जो यह प्रयोग किया वह बिल्कुल ही असफल साबित हुआ। सरकार को केवल 17-18 लाख टन ही गेहूँ इस साल मिला और इससे ज्यादा गेहूँ सरकार को प्राप्त नहीं हो सका बल्कि मीडियों में भी गेहूँ नहीं आया। सरकार की ओर से जो प्रकाशित आंकड़े हैं उसके हिसाब से 1973-74 में यानी पारसाल 40 लाख टन गेहूँ मीडियों में आया और 43-44 लाख टन गेहूँ सरकार ने खरीदा। इस साल मीडियों में 31 लाख टन गेहूँ आया और 17-18 लाख टन गेहूँ सरकार ने खरीदा। ये आंकड़े 24 अगस्त तक के हैं और इसके बाद के आंकड़े मरे पास नहीं हैं। जब सरकार ने गेहूँ का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लिया था तो जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जो उनके दोस्त थे, उनके सहयोगी और समर्थक जितने राजनीतिक दल थे, उन लोगों ने हिन्दुस्तान भर में शोरगुल मचाया, यह हंगामा मचाया कि सरकार ने एक गलत काम किया है। उस समय भी सरकार ने इन अड़चनों के बावजूद 44 लाख टन गेहूँ प्राक्चार किया था जिस के कारण पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जारी रखा जा सका। लेकिन इस साल तो गेहूँ का व्यापार सरकार ने थोक व्यापारियों के हाथ में दे दिया और उनकी भलमनसाहत और आश्वासन पर भरोसा किया। उन्होंने सरकार को यह भरोसा दिलाया था कि वह गेहूँ सरकार को दे देंगे, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार को गेहूँ नहीं मिला और दाम भी इतने बढ़ गये जितने कि पिछले वर्षों में

कभी भी नहीं बढ़े थे। गेहूँ के भाव सरकार ने 105 रुपये क्विंटल रखा था, और व्यापारियों ने 10-20 रुपये ज्यादा देकर गारा गेहूँ खरीद लिया और अब वह गेहूँ बाजार में 300, 400 और 500 रुपये क्विंटल में बिक रहा है। हमें इस बात का आश्चर्य होता है कि जितने भी राजनीतिक दल थे लोग थे, जिन्होंने सरकार से आग्रह किया था कि गेहूँ का थोक व्यापार उसको छोड़ देना चाहिये, हम तुम को गेहूँ दिलवा देंगे, वे आज इस बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं, वे लोग चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। वे लोग इस महंगी का बहाना बनाकर असम्बली भंग करने की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट का घेराव करने की बात कर रहे हैं और आल इंडिया रीडियों का घेराव करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के जो राजनीतिक दल वाले लोग हैं, इन लोगों की इस बारे में एक साजिश है। हमारी सरकार से यह शिकायत है कि उसने इन लोगों की साजिश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है जिसके कारण भुखमरी हो रही है और लोगों का परेशानी हो रही है तथा सरकार को विदेशों में जाकर गेहूँ के लिये दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है और ऊंचे दामों पर गेहूँ खरीदना पड़ रहा है।

मैं विश्वास करता हूँ कि अभी भी जिस रेट पर हमारे देश में गेहूँ सरकारी दुकानों पर मिलता है उससे ज्यादा दाम पर सरकार को विदेशों से खरीदना पड़ता है और फिर सब-सिडी देनी पड़ती है। ये सब परेशानियाँ इस कारण पैदा हो रही हैं कि सरकार ने थोक व्यापार को त्याग दिया और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को नुकसान पहुँचाया।

अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री ने दूसरे सदन में बोलते हुए एक और तथ्य को स्वीकार किया है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत सा अनाज बड़े बड़े जमींदारों और भूमिदारों ने छिपा कर रख लिया है।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा (उत्तर प्रदेश) : वह रणबीर सिंह के पास होगा।

श्री इन्द्रदीप सिंह : पता नहीं किन-किन के पास होगा। बहुत से लोगों के पास होगा। कृषि मंत्री ने नहीं कहा है :—

The shortage was not as much as it was shown to be because the rich farmers were holding on to their stocks in the expectation- that they would get a higher price". (Synopsis of Debates— Page 90)

यह कृषि मंत्री ने खुद स्वीकार किया है। कृषि मंत्री ने इस बात का दावा किया कि हमने इस छिपाए हुए अनाज को पकड़ने के लिए जो अभियान चलाया है उसमें एक लाख टन अनाज पकड़ा है।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : कोलछाँज बनवाए।

श्री इन्द्रदीप सिंह : कोलछाँज (सामूहिक छंती) बनवानी पड़ेगी एक दिन। एक लाख टन अनाज आपने निकाला लेकिन कितना छिपा कर रखा हुआ है? मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि कुछ अनुमान तो बताए कि कितना छिपा कर रखा हुआ है। जैसा कि एक सदस्य ने कहा, 55 हजार छापे मारे गए और एक लाख टन अनाज मिला। एक छापे पर कितना एचरेंज पड़ा यह आसानी से निकाला जा सकता है। इसमें पता चलेंगा कि यह बहुत छोटी मात्रा है। छापों में क्या हाँसी है? छापों से पहले पुलिस अधिकारी गल्ला चोरों को खबर दे देते हैं कि तुम्हारे यहाँ छिपा भरण आ रहे हैं। छिपा भरण का काम या छिपा हुआ अनाज निकालने का काम तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसमें जनसहयोग न लिया जाय।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : सी. पी. आई का सहयोग लिया जाय।

श्री इन्द्रदीप सिंह : आपका भी सहयोग हम लेने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि आप गल्ला-चोरों की ओर न हाँकर बनता की ओर हों। हम सरकार से कहेंगे कि अगता की ओर जितने दल के लोग हों उनका सहयोग लें, लेकिन जो लोग गल्ला चोरों के काम में बताएँगे कि तुम्हारे यहाँ रहे हैं वाला है उनका सहयोग नहीं लेना

चाहिये। इसलिए मंत्री स्पष्ट राय है कि जो भी दल गल्ले के धाँक व्यापार के पक्ष में नहीं है उनको अन्न सहायका समितियों में नहीं बैठने देना चाहिये क्योंकि वे तो दुर्निवादी नीति के ही पक्के हैं। इन समितियों में उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो गल्ले के धाँक व्यापार को सरकार के हाथ में रखने और सरकारी दकानों

अन्न मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि देश में जो असमानता की स्थिति फैली हुई है वह आज की नहीं है बल्कि जनक वर्षों से विकसमान है और सरकार उसको दूर करने में सफल नहीं हुई है। जिस कृषि शब्दवली का इस्तमाल अन्न मंत्री महादेव ने किया है उससे निकल कर साफ शब्दों में हम कहते हैं कि गाँव के अन्दर मूट्टी भर भूस्वामियों के हाथ में जो जमीन का केंद्रीकरण है जबकि अधिकांश लोग भूमिहीन हैं या उनके पास बहुत कम जमीन है वही प्रधान कारण है अन्न संकट का। जमीन के इस केंद्रीकरण के कारण गाँव में मूट्टी भर लोगों के हाथों गरीबों का शोषण हो रहा है और अनाज की पैदावार भी घटी है। जो अनाज पैदा होता है उसको वे लोग छिपा कर रख लेते हैं और जब तक चोर-बाजार का दाम नहीं मिलता उस अनाज को बाजार में आने नहीं देते।

"The conditions that existed today were the accumulation of the economic and social conditions that existed in the country for years. It had not been possible to disentangle ourselves from the inequitous social set-up in the country that affected agricultural production as well".

[श्री इन्द्रदीप सिंह]

यह आश्चर्य की बात है कि कृषि मंत्री स्वीकार करते हैं कि यहाँ यह परिस्थिति है और वर्षा से बनी हुई है और हम इस परिस्थिति को दूर नहीं कर सकते, तो आप क्या हैं वहाँ पर ? अगर यह परिस्थिति है और वर्षा से बनी हुई है और आप जानते हैं कि इसको दूर नहीं कर सकते तो आप क्यों वहाँ बैठे हुए हैं ?

श्री ओम प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश) : क्योंकि आपको हमदर्दी है ?

श्री इन्द्रदीप सिंह : हमारी हमदर्दी यह है कि हम उनकी आँख में लंगली डालकर बतलाना चाहते हैं कि आपको यह काम करना होगा। नहीं करेंगे तो उनको हटाकर हम उन लोगों को वहाँ बैठाना चाहते हैं जो इसको कर सकें और उन लोगों में आप लोग नहीं हैं, क्योंकि आप लोग उनके साथ हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है। आप जमीन को समेटकर बैठे हुए हैं।

श्री रणवीर सिंह : जो लाठी दल है वह भी उसमें नहीं है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : सी. पी. आइ. उसमें हैं क्योंकि सी. पी. आइ. माने चमचा पार्टी आफ इंडिया।

श्री इन्द्रदीप सिंह : हम इंडियनों की जनता की पार्टी है, गल्ला चोर की चमचा पार्टी नहीं। गल्ला चोर और नकाशों की पार्टी को उरा सरकार में नहीं होगा चाहे।

उप-समाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं अन्त में निर्वादन करूंगा कि सरकार को अभी भी इस सूखती को त्यागना चाहिए और इतना बड़ा अभाव जो फैला हुआ है, इस प्रकार की भूख-मरी जो फैली हुई है, देश में इतना असन्तोष जो फैला हुआ है, उसको सामने रखकर अभी भी भूमि सुधारों का जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिये कदम उठाने चाहिए। अभावग्रस्त क्षेत्रों में भूमिसुधारों से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि भूमि सुधार होगा उसके बाद अनाज की पैदावार बढ़ेगी, उसके बाद गरीबों के घर में

अनाज होगा। तो आज तत्काल आवश्यकता है कि जितने भी अभावग्रस्त क्षेत्र हों वहाँ पर शीघ्र से शीघ्र अनाज पहुँचाया जाए और जितना भी अनाज छिपाकर रखा हुआ है उसके लिये एक देशव्यापी अभियान चलाकर तमाम छिपे हुए गल्ले को निकाला जाये।

उप-समाध्यक्ष महोदय, अखबारों में हमने पढ़ा कि यहाँ पर कुछ दोस्त लोग झूटठा हो रहे हैं, फील्ड्समॉन्ट का घेराव करने के लिये, आल इंडिया रीडियों का घेराव करने के लिये मैं सरकार से और शासक दल से कहूँगा कि आप नारा दीजिए 'गल्ला चोरों का घेराव करो' और जय प्रकाश नारायण से कहें कि अगर गरीबों के लिये कोई माह्वत तुम में है तो तुम हम चलते हैं नकाशों और गल्ला चोरों का घेराव करने के लिये तुम हमारा साथ दो।

धन्यवाद।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चंडावत (राजस्थान) : उप-समाध्यक्ष जी, इन पिछले वर्षों से कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि अकाल हमारे देश का एक अंग बन गया है। पहले तो हम यह सोच करते थे कि शायद राजस्थान ही एक ऐसा अभाग्य प्राप्त है जहाँ पर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ जाता है। लेकिन अकाल आजकल हमारे देश का एक अंग बनता जा रहा है। सबसे ताज्जुब इस बात को लेकर होता है कि जिस देश में दिनियाभर के पानी का 10वाँ हिस्सा ही, उसमें हर साल अकाल कैसे पड़ जाता है। दूसरा हमारे यहाँ की जो नदियाँ हैं वह हर साल 1,350 एकड़ फीट पानी बहाकर समुद्र में ले जाती हैं और हम अपने यहाँ जो पानी के सोर्सेज हैं उनका तीसरा हिस्सा मुश्किल से इरिगेशन सिंचाई के लिये काम में ला सकते हैं, बाकी सारा का सारा पानी बेकार समुद्र में बहकर चला जाता है। इसका मतीजा यह होता है कि इधर हमारे यहाँ फलड हर साल किसी न किसी रूप में 2-3 राज्यों में आते रहते हैं और बाकू में जो नुकसान होता है उसका मोट्टे तौर से हम हिस्सा लगाएँ तो 12९ करोड़ रुपये का नुकसान चाहे फसल की नजर से है, चाहे मिर्चिकयल की नजर से है, हर साल ही आता है और जान का नुकसान उसके अलावा

है। तो जब हमारे मुल्क में इतना पानी है, इतने फलड होकर नुकसान होता है, इतनी ज्यादा मात्रा में पानी समुद्र में चला जाता है, अगर उसी पानी का हम ठीक ढंग से सदुपयोग कर सकें, उसे सिंचाई के लिए काम में ला सकें तो समझ में नहीं आता कि हिन्दुस्तान में कोई अकाल कैसे रह सकता है। रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब दुर्भाग्यवश स्थिति यह है कि आज 72 जिलों में अकाल पड़ा हुआ है। एक नहीं कई राज्यों में मिल कर आन्ध्र, हरियाणा, बिहार, राजस्थान इत्यादि में 13 राज्य आज अकाल की चपेट में हैं। मैं आपको एक नमूना देना चाहती हूँ कि हमारे पास जो एक विशाल जलाशय है उसके लिए हम अपनी पूरी प्लानिंग पूरी करके अपने पूरे रिसोर्सिज इसके सदुपयोग के लिए लगाए और कामों का छाड़ दें।

आज हमारे मुल्क के सामने सबसे कठिन परिस्थिति जो है वह अन्न की है। आज हमारे मुल्क के सामने सब से बड़ी समस्या जो है वह अन्न की बढ़ती हुई कीमती की। अगर इन दोनों चीजों का कंट्रोल कर सकते हैं तो मैं समझती हूँ इस वक्त हमारे सामने कोई दूसरी समस्या नहीं रह जाएगी। जब हम अपने पानी के रिसोर्सिज के बारे में सोचते हैं तो फंड की बात आती है। मैं मानती हूँ कि इसमें बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। इसके अलावा हम लोगों की अपनी भी कुछ खामियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं। आज कई प्रोजेक्ट हमारे हाथ में हैं। आज बहुत सी नदियों की प्लानिंग हम लोगों ने कर रखी है। नर्मदा, गाँदावरी, कावेरी और पार्वती आदि नदियों की प्लानिंग हमने कर रखी है। लेकिन आपस के राज्यों के भूगडों में थोड़े डिस्प्यूट में पड़ी हुई हैं। एक नहीं बड़े-बड़े प्रोजेक्ट 10 साल से चले आ रहे हैं, 15 साल से चले आ रहे हैं अगर हम उन डिस्प्यूट को सुलभ कर सकें होते उनका उस वक्त देवा दिया जाता तो आज वह स्थिति पैदा नहीं होती।

नर्मदा का भूगड आज तीन राज्यों के बीच में है वह पता नहीं कब का पड़ा हुआ है। इसी

तरह कृष्णा का एवाड मिल गया लेकिन फिर भी उसमें भूगड चल रहा है। इसी तरह कावेरी का लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में भूगड है। गाँदावरी का लेकर महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में भूगड चल रहा है। माहि का लेकर राजस्थान और गुजरात में भूगड है, यह कोई नहीं कह सकता कि केंद्रीय सरकार भी यह नहीं कह सकती कि यह कोई बाहर का मामला है इसलिए हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि यह मामला हमारे अपने राज्य के बीच में है इनका समझौता हमें कर लेना चाहिए, वाटर डिस्प्यूट को खत्म करना चाहिए। मैं तो यह कहूँगी कि जो हमारे वाटर रिसोर्सिज हैं उनको गैरनॉन-कॉन्सुमिबल किया जाए ताकि इन राज्यों के बीच के भूगड खत्म हों। केंद्र के पाँच आदमी बैठकर, जैसा ठीक समझे उसें सुलभ कर सकते हैं। आप जानते हैं इनके सुलभाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है। उनमें लाखों-करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। बड़ी-बड़ी, ऊंची तनखवाहों के आदमी उनमें हैं, वकील लाए जाते हैं, केंद्र का अनाप-शनाप पैसा उसके लिए खर्च होता है और उसका नतीजा यह निकलता है . . .

SHRI ANNASHEB A SHINDE: The Chair feels that tribunals don't find solutions.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूड़वंत : मैं मंत्री महोदय से कहूँगी कि आपको जो एवाड पड़े हुए हैं उनको निकालिए, फँसला करिए। जहाँ जहाँ पानी देना है वहाँ दीजिए। सारे राज्य हिन्दुस्तान के अंग हैं। यह हो सकता है कि कहीं पर अच्छी जमीन है लेकिन आप उनको वक्त पर पानी नहीं दे पाए जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसी की एक मिसाल अपने राजस्थान कॅनल को देना चाहती हूँ। यह कॅनल आज 8 साल पहले खत्म हो जानी चाहिए थी लेकिन पूरे रिसोर्सिज न भेजने के कारण अभी तक उसका पहला चरण, फर्स्ट स्टेज भी पूरी नहीं हो पाई है। आज अगर राजस्थान में कॅनल को पूरा कर लिया जाता तो राजस्थान में जो स्थिति आज है वह न होती। आज वहाँ अकाल होने के कारण हर साल 30 लाख पशु जो एडरड हैं वे यहाँ से माइग्रेट होकर

[श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत]

चल जाते हैं। यह आपके आंकड़े बताते हैं। लाखों पशुधन हर साल आने-जाने में भूख से मर जाते हैं। यह अन्दाजा लगाया गया कि इस पशुधन के मरने से हमारा राष्ट्रीय नुकसान बढ़ा अबर्दस्त हो रहा है।

अगर आप चाहते हैं कि हमारी इकनोमी में सुधार हो और हमारे देश की फूड प्रॉब्लम हल हो तो यह बहुत आवश्यक है कि हमारे देश में जो एरिड एरिया हैं, जैसे कच्छ, चाड़मर, जेसलमेर और बीकानेर आदि का क्षेत्र है और जो बहुत लम्बा चौड़ा एरिया है वहां पर एग्रो-इंडीस्ट्रियल आधार पर कुछ काम किया जाना चाहिए। वहां पर जो पशुधन है, शीपें हैं, उनकी चमड़ी, हड्डी और जो मिलक प्रोडक्ट है, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा जानवरों के सींगों और खुरों के उपयोग के लिए भी कारखाने लगाए जा सकते हैं। वहां पर फंडर की एक बड़ी समस्या बनी रहती है। मैं समझती हूँ कि इस क्षेत्र को एक बड़े बरसात में भी बदला जा सकता है। बरसात के अन्दर जब वहां पर थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है तो घास उग आती है। इसलिए उस घास को काटकर फंडर बॉक कायम किया जा सकता है। अगर इस प्रकार से योजनाबद्ध रूप से काम किया जाय तो कोई कारण नहीं है कि हम इस सूखे और अकाल की स्थिति से निपट पाएं।

मैं यह मानती हूँ कि हमारे देश में अन्न की कमी है। सरकारी आंकड़े जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे देश में सिर्फ 2 प्रतिशत अन्न की कमी है। ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उठता है कि इस दो प्रतिशत की कमी को हम अपने देश में अन्न की बरबादी को बचाकर क्या पूरा नहीं कर सकते हैं? निश्चय ही हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि हमारे देश में बहुत सा अन्न तो चूहे ही खा जाते हैं। जो अन्न हम विदेश से मंगाते हैं और उस पर जो पैसा खर्च करते हैं उसके अगर देश में ही अन्न की पैदावार बढ़ाने और चूहों आदि से अन्न की बरबादी रोकने में लगा

दें तो हम इस दो प्रतिशत की कमी को पूरा कर सकते हैं। चूंकि कबल दो प्रतिशत अन्न की कमी है, लेकिन फिर भी विदेशी मुल्कों के अन्दर हिन्दुस्तान का बदनाम किया जाता है।

आज हमारे विरोधी दल के लोगों के हाथों में भी एक हथियार आ गया है और वे इस देश को बदनाम करते रहते हैं कि इस देश में लोग भूखों मर रहे हैं। हमारे देश को जिस तरह से आज विदेशों में बदनाम कर रखा है उससे बहुत बुरा लगता है। मेरी लड़की यू. कं. में है और वहां से पत्र लिखती रहती है कि यहाँ के अखबारों में हिन्दुस्तान की बहुत बुरी हालत बताई जाती है। ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान में लोगों को खाने के अन्न नहीं मिलता है। उसके पत्रों से मुझे ऐसा नजर आता है कि उसके दिमाग में एक तस्वीर बन गई है कि शायद उसकी मां वां भी हिन्दुस्तान में खाने के अन्न का खाना मिलता भी है या नहीं। इस प्रकार का प्रचार वहां पर पत्रों में हो रहा है। आपने इस वक्त जो डिहंगीडंग का अभियान चला रखा है, इसका आप चलाए रहेंगे मैं समझती हूँ कि अगर आप डिहंगीडंग अच्छी प्रकार से पूरी सख्ती से करेंगे तो हम बहुत कुछ अन्न की दिक्कत को दूर करने में सफल हो सकते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि डिहंगीडंग करने के लिए हमारे फूड मिनिस्टर ने कदम उठाए हैं। इस संबंध में उन्होंने जिस तरह से राज्य सरकारों को चेतावनी दी है, उसका एक असर पड़ा है और अन्न की वसूली हो रही है। अब राज्यों के चीफ मिनिस्टर भी इस बात को महसूस करने लगे हैं कि बार-बार केंद्रीय सरकार से अन्न की मांग करने के बजाए खुद ही अन्न की वसूली की जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं इस बात को भी मानती हूँ कि अन्न को बाहर निकालने के लिए जितनी पूरी चेष्टा की जानी चाहिए उतनी नहीं की गई है इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस दिशा में हम सख्त कदम उठाएं।

अन्न की समस्या पर यहाँ पर हर साल बहस होती है, लेकिन फिर भी यह समस्या हल नहीं

हंती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जितने भी रिसोर्सज हैं, जैसे एरिगेशन है या अन्य साधन हैं, उनका पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह वैज्ञानिक दृष्टि है। उत्तर प्रदेश में जो हंगरी के पम्प लगाए गए हैं वे 10 मील तक पानी को फेंकते हैं। अगर इसी प्रकार की योजना बनाई जाए तो वॉर्ड कारण नहीं है कि हम देश की अन्न की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की योजनाओं से काफी दूरी तक पानी पहुंचाया जा सकता है। मंत्री महोदय ने यह भी बताया है कि सर्वोत्तम करने से यह पता लगा है कि राजस्थान के अन्दर अन्डरग्राउन्ड वाटर काफी मात्रा में मिला है। बहुत खुरी की बात है लेकिन अंडरग्राउन्ड वाटर को हम बाहर निकाल दें, उस को टैप कर के उसके चुटिलीट्टी के काम में लाएं तभी कुछ होगा। इस समय हमारी सरकार की पालिसी इस ओर लगी है कि हम चहुंमुखी, सर्वतोन्मुखी, प्रगति कर लें, और ठीक भी है, लेकिन इसका नतीजा यह निकला कि किसी एक लाइन में हम तरक्की नहीं कर पाए। मैं स्पष्ट रूप से जोर देकर कहती हूँ, इधर-उधर की तरक्कियाँ, इधर-उधर के खर्चों से राकड़ दिए जाएं और देश को सामान्य जो अहम प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न है फूड का और उसमें प्रॉडक्शन कम होने से कीमती ऊंची हुई है, इस परिस्थिति का पूरी ताकत के साथ, सारी शक्ति उसमें लगा कर मुकाबला किया जाए और राजनीतिक तौर पर भी इसका मुकाबला किया जाए। राजनीतिक तौर पर हमारी पार्टी जनता को साथ लेकर, उसका सहयोग लेकर और जो जनता इसमें सहयोग करना चाहती है उनको अपने साथ लेकर ऐसी जांच समितियाँ बनायी जाएं कि जिन लोगों ने सामान इकट्ठा कर रखा है, उन के सामान को डीहॉल्ट कर सकें। आज जानबूझ कर प्रॉडक्शन गिराया जा रहा है नफा कमाने के लिए। उस पर अनुशासन लाया जाए। हमारे सामने यह दिक्कत है कि धराव हाते हैं, सभार्य हांती हैं, और वे कुरुक्षेत्र के मैदान राजाना बनते हैं। सबसे जड़ की चीज यह है कि लोगों को खाने को मिले और सस्ती कीमत पर मिले—ठीक भाव पर भी मिले और ठीक मात्रा में पहुंच जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ की जो

सर्वतोन्मुखी या चहुंमुखी प्रगति की जो बात है उसे साल दो साल के लिए बंद कर दिया जाए और केवल एक प्रगति में अपनी सारी शक्ति लगा दें और वह है रोजी, रोटी, कपड़ा और जरूरत की सारी चीजों जनता को आसानी से मिल जाए।

श्री जगवीर सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं राजस्थान की सदस्या जो अभी बोल रही थीं उनको बधाई देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि यह सरकार यह बचन दे कि जितनी बातें उन्होंने कही हैं उनको पूरा कर देंगी तो मुझे कुछ कहने का बाकी नहीं रह जाता।

यह जो बहस आज है भुवनेश्वर पर, स्टार्वेशन डेथ्स पर, फेमीन पर, इस संबंध में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ और वह यह है कि आज यह निर्विवाद सत्य है कि हमारे देश में कुछ अंचलों में भुवनेश्वर है। यह भी निर्विवाद सत्य है कि हमारे वहाँ फेमीन कंडीशंस हैं। यह भी निर्विवाद सत्य है उपसभाध्यक्ष महोदय, कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ईस्टर्न बंगाल, और असम में स्टार्वेशन से डेथ्स हुई हैं। मंत्री महोदय गाने या न मानें यह तो उनकी मर्जी है लेकिन सच्चाई पर परदा डालना कोई आसान बात नहीं है और न छिपाई जा सकती है। मुझे एक बात याद आ गई। मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता कि वेस्ट बंगाल में कितनी माँतें हुई हैं, कितनी असम में हुई हैं, कितनी ईस्ट बंगाल में हुई हैं, केवल दो तीन बातें कहना चाहता हूँ कि आल पार्टी डेवेलोपमेंट जो गया था उसके अनुसार 25,000 माँतें बतायी जानी हैं। मैं केवल दो-तीन आदीमियों ने जो इस संबंध में कहा है उसके बारे में कहूंगा। वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने कहा है :

“People are living on grass roots”.

यह हालत है कि घास रूट्स पर वेस्ट बंगाल का आदमी रहता है। क्या इन्सान हांकर घास खाएगा, यह एक सोचने का विषय है सरकार के लिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, नूरुल इस्लाम

[श्री जगवीर सिंह]

साहब जाँ कि जनरल सेंक्रेटरी हूँ वेस्ट बंगाल प्रदेश काँग्रेस कमिटी के उन्होंने कहा है :

"Starvation deaths had been reported to the Committee from different parts or the State".

मैं नहीं जानता कि आपका काँग्रेस का जनरल सेंक्रेटरी असत्य बात कहता है। मैं यह भी नहीं जानता कि वहाँ का गवर्नर असत्य बात कहता है। महादय, इतना ही नहीं, वहाँ के एक मंत्री महादय संतोष से ने कहा है :

"Fifteen million people in the rural areas of West Bengal are either starving or living on one meal a day".

वेस्ट बंगाल की सरकार का मंत्री इस बात को कहें और उसके बाद भी हमको शरम लगती है इस बात के मानने में कि वेस्ट बंगाल के अंदर भूखमरी से मौतें हुई हैं, मैं नहीं समझता कौन सा परदा सरकार के सामने है कि इस बात को स्वीकार करें। हम को सत्य स्वीकार करना ही चाहिये। एक कहावत है "चोर की दाड़ी में तिनका"। कुछ लोग बँठे हुए थे। किसी ने कहा जाँ कि चोर है उसकी दाड़ी में तिनका है। जाँ असल में चोर था वह अपनी दाड़ी में हाथ लगाने लगा कि कहीं कोई तिनका तो नहीं है। वही हालत आज हमारी सरकार की है। हमारे श्री जगजीवन राम जी, जिनके पाव फुड का मुहकमा है, उन्होंने रोम में कहा था :

He had no figures of hunger problem in India but he did not think that the people have starved to death.

इस तरह की बात का कहने की उन्हें क्या आवश्यकता थी ? उन्होंने यह भी कहा :

They do not get good quantity of nutrition.

इन बातों से यदि सारांश निकाला जाए तो यह निकलता है कि हमारे देश में स्टारवेंशन से डँथ हुई है। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने जाँ स्टैटमेंट दिया है उसमें कभी भी यह बात स्वीकार नहीं की है कि देश में स्टारवेंशन से डँथ हुई है बल्कि इन्होंने यह कहा है कि हमारे देश में

फौमिन कंडिशनस हैं। मुझे उनका एक बान चाद आता है जाँ उन्होंने अपने पिछले जन्म दिन के अवसर पर एक विदेशी सम्बाददाता को दिया था। उन्होंने यह कहा था :

There are people who used to pick grain from the dung. Now they get at least one meal a day. That is* enough.

जिस देश के प्रधान मंत्री के सोचने का यह तरीका है कि पहिले हमारे देश के लोग गाँव में से दाना उठाकर खाते थे और अब तो उनको एक वक्त खाना पड़ता है जाँ कि काफी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और विशेष कर मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ढंग से सोचने वाला प्रधान मंत्री क्या देश की अनाज की समस्या को हल कर सकता है जब कि हमारे देश में बंगाल, उड़ीसा और आसाम में स्टारवेंशन से लोगों की मौतें हो रही हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें, प्रधान मंत्री विचार करें, सरकार विचार करें कि इस समस्या को हल करने के लिए किस तरह से कार्य किया जाना चाहिये। इतना ही नहीं अगर आज हमें हालत की तुलना करनी है तो 1943 के फौमिन के बाद पहिली बार हमारे देश में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जाँ से मौतें हुई हैं हमारे देश के अन्दर, उनमें कौन लोग मरें ? क्या हमारे चाँधरी रणवीर सिंह जी का वजन कम हो गया ? नहीं। क्या मंत्री जी का तकलीफ हुई है ? नहीं। तकलीफ हुई है गरीब आदमी को। माल न्यूट्रेशन की बात कही जाती है और इस बारे में बहुत से अखबारों का हवाला दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं भी इस सम्बन्ध में दो अखबारों का उल्लेख दे सकता हूँ। चंडीगढ़ से ट्रिब्यून ने कहा है :

"The average Indian's share of food had been worked out to 2100 calories and 52 grains of protein every day against the minimum requirement of 2357 calories and 44.5 grams of protein-an official spokesman said on 21-10-73".

इतना ही नहीं हिन्दुस्तान स्टारवर्ड नं कहा है :

The calories content of Indian diet is the lowest in the world—only 1,81, calories a day.

ठीक है, माल न्यूट्रेशन की बात हमने मान ली और मंत्री जी कहते हैं कि हमारे यहाँ स्टारवर्डन से डेथ नहीं हुई है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि माल न्यूट्रेशन में जो डेथ हुई है क्या उसका स्टारवर्डन डेथ नहीं माना जायेगा ? अगर एक आदमी को कहीं दिनों से माल न्यूट्रेशन नहीं मिलेगा, उसे कम भोजन मिलता है और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका स्टारवर्डन से डेथ नहीं माना जायेगा ? हमारे मंत्री जी कहें कि हम पूरा अनाज नहीं दे सकते हैं, पूरी खुराक नहीं दे सकते हैं, तो फिर इसके अन्दर इतनी परेशानी क्यों है और इसमें आपत्ति क्या है और न इससे कोई पहाड़ ही टूटने वाला है ।

It is a fact which cannot be denied with lame excess.

मरा कौन है ? शहर में रहने वाला नहीं मरा है । एक मित्र कह रहे थे कि सिनेमा पर भीड़ क्यों है । सिनेमा पर भीड़ होगी दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई के अन्दर । ग्राम के अन्दर जो व्यक्ति रहता है उसका पैसा फिल्म देखने पर खर्च नहीं होता । मेरी पहले भी शिकायत थी और आज भी शिकायत है कि सरकार के त्रिष्टकाण में अन्तर है गांव और शहर में रहने वालों के बीच । अन्न की कमी से गांव में रहने वाला व्यक्ति मरा है, गरीब आदमी मरा है । मालदार आदमी जो पिकचर देखने जाता है वह स्टारवर्डन से नहीं मरा है ।

हमारे देश के अन्दर गरीबी क्यों है ? 1971 में नारा दिया गया 'गरीबी हटाओ' गरीबी हटाओ का नारा देने के बाद आज कहते हैं कि परचीजंग कर्पीसटी नहीं है, परचीजंग पावर नहीं है । इसके लिए कौन जिम्मेदार है । मैं आप के माध्यम से जानना चाहता हूँ, अधिष्ठाता महोदय, कि इसके लिए वह सरकार जिम्मेदार है या नहीं जो 27 साल से बराबर कर्सी में

चली आ रही है और आज कहती है कि हमारे देश में लोगों के पास पैसा नहीं है । दांनों में कन्ट्रीडकशन है । क्या इस देश के अन्दर गल्ला कम है या परचीजंग कर्पीसटी नहीं है ? क्या हम गल्ला सबका खाने के लिए पूरा दे सकते हैं ? अगर दे सकते हैं तो उसके बाद सवाल आता है कि परचीजंग कर्पीसटी है या नहीं है । ये दांनों में कन्ट्रीडकटरी बातें हैं ।

गरीबी हटाओ का नारा इन्दिरा जी ने बाद में दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार का बराबर प्रयत्न रहा होगा कि देश में गरीबी दूर हो, कभी सरकार का यह प्रयत्न नहीं रहा होगा कि इस देश के अन्दर गरीबी बढ़े । मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि फिर भी ऐसे व्यक्ति जो बिलों पावर्टी लाइन कह जा सकते हैं जिनकी आमदनी 20 रुपये प्रति माह भी नहीं थी 60-61 की प्राइमरी के हिसाब से उनकी तादाद देश की कुल आबादी की 2/3 थी 67 में आज वह 72-73 में 2/3 हो गई है जबकि बिड़ला और टाटा की सम्पत्तियां कहीं गुना बढ़ गई हैं । इस देश के अन्दर अगर इस प्रकार गरीबी हटती रही तो वह दिन दूर नहीं जबकि सब सम्पत्ति दादा और बिड़ला, और 75 परिवारों के हाथ में पहुंच जायेगी, जो इस देश में राज करेंगे ।

अधिष्ठाता महोदय, इस बहस में हमको देखना यह पड़ेगा कि आखिर कारण क्या है जिनकी वजह से आज देश के अन्दर यह स्थिति उत्पन्न हुई है । मैं बहुत सफाई से कहना चाहता हूँ कि इस स्थिति के उत्पन्न होने का कारण केवल एक है कि हमने महात्मा गांधी के सिद्धान्तों का छोड़कर और सिद्धान्त अपनाए हैं । महात्मा गांधी ने हमेशा यह कहा था :

Agriculture first, small-scale industries second and heavy industries afterwards.

लेकिन '55 में आन्ड्री के रेशन के बाद नेहरू जी के आग्रह पर प्रायोरिटीज बदली गई । पहले प्लान में कृषि के उत्तर 27 प्रतिशत एक्सपेंडीचर हुआ था, जिसको घटाकर दूसरे प्लान में 21 प्रतिशत कर दिया गया और करीब वही 21 प्रतिशत आज तक चला आता है—थोड़ा बहुत डीकेशन

[श्री जगदीर सिंह]

हो सकता है, लेकिन करीब करीब वही। मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि सबसे बड़ा कारण यह है कि कृषि को जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। यह सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश को अन्दर आज यह स्थिति उत्पन्न हुई।

इतना ही नहीं, मैंने पहले शायद कहा था या नहीं, मैं एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ कि मंसू आज भी विश्वास है कि देशांत के अन्दर हिन्दुस्तान रहना है। महात्मा गांधी ने कहा था :

"India lives in the villages".

आज जो असली हिन्दुस्तान है वह देशांत के अन्दर है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ते के अन्दर नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि इस बीच में जो हमारी पालिसी रही है क्या उस पालिसी से गांव और शहर की विषमता को हमने बढ़ाया है। जो गरीब पहले ही गरीब था क्या उसको गरीबी और बढ़ी है और मालदार की मालदारी बढ़ी है या नहीं। अधिष्ठाता महादय, फ्रॉन्टियर-रिजिनी इकानामिस्ट हैं। उन्होंने कुछ आंकड़े दिये हैं, मैं उनको आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है—

पहली प्लान के आखीर में गांव और शहर की आमदनी का अन्तर—गांव वालों की आमदनी कल आमदनी की 27 प्रतिशत थी जब कि वह घटकर दूसरे प्लान के अन्त में केवल 24 प्रतिशत रह गई और तीसरी प्लान के अन्त में 20 प्रतिशत और 1966-67 में 18 प्रतिशत। उसके बाद के 3 साल के आंकड़े मौजूद नहीं हैं, हाँ भी तो वह मुझे उपलब्ध नहीं हो पायें। तो मैं यह कह रहा था कि हमारी सरकार की मौलिक नीति जो है वह इस प्रकार की है जिसमें इस स्थिति को उत्पन्न कर दिया।

अब सरकार को चाहिए कि सरकार बहुत बहादुरी के साथ इस स्थिति का सामना करे। आज कहा जाता है कि वाच् जगजीवन राम जी के हाथ में यह विभाग आया है, वह जिस महत्कर्म में गवां हैं उसमें उनको पूरी सफलता मिली है, मैं चाहता हूँ कि ईश्वर करे यहां भी उनको सफलता मिले, कि यह देश बच सके, न केवल

मजदूर बच सके, ग्रहों का गरीब आदमी बच सके, यहां का गांव वाला बच सके, यहां के बहनों के इज्जत बच सके जिन्होंने बच्चों को बचकर राटियां खाई हैं।

(Time Bell rings)

मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। गवर्न-मेंट की तरफ से कई बातें कहीं गई हैं। लेकिन हमें देखना होगा कि आखिर इन 27 वर्षों के अन्दर कितना ज्यादा अनाज पैदा हुआ, कितनी ज्यादा जमीन को हम खेती के अन्दर ला पाये हैं, कितनी ज्यादा जमीन पर हम खेती कर सके हैं, क्या हमने किसानों को इंसेंटिव दिये हैं अनाज पैदा करने के लिए यह सवाल है जिन पर विचार करना होगा।

अधिष्ठाता महादय, आज इस स्थिति का हल केवल इनकीज्ड प्रॉडक्शन हो सकता है। यह नहीं हो सकता है कि हम विदेशों में जाकर भीख मांगें। वाच् जगजीवन राम ने जो कहा कि मैंने तो मंसू में टंकनालाजी देने की बात का जिक्र करते समय अपने देश का नाम लिया। प्रधान मंत्री जब कनाडा में गईं, तो वहां पर टेलीविजन में दिखाया गया, वहां के आदीमियों को, भूख भरते हुए। हमारे देश की इज्जत विदेशों में घटी या नहीं? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी अगर आप इस देश को बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यहां का आदमी खुशहाल हो, आपके पास रिसोर्सिज हैं, आप पैदावार बढ़ाकर इस देश की हालत सुधार सकते हैं। आप दूसरे देशों से अनाज मंगाकर सुधार सकते हैं, ऐसा मंसू विश्वास नहीं है।

अधिष्ठाता महादय, आज ही एक इकानामिस्ट की एक किताब मुझे मिल गई। उन्होंने कहा है—

"The need for increased fertilisers has been so obvious that I simply cannot understand the failure to provide them in sufficient quantities".

लेकिन आज हालत क्या है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी गांव से आता हूँ कि आज किसान तैयार नहीं

हैं आपकी बढ़ी हुई कीमतों पर खाद खरीदने के लिए। आज किसान सोचता है इस बात को। आपने नहीं कहा है कि आप कीमतों में कितनी वृद्धि करेंगे अगले साल में। अगर आपने बतला दिया होता किसान को कि हम इतना पैसा देंगे अगली फसल के लिए तुम खूब पैदा करो तो इस देश में वे भूखे नहीं मरने देंगे। अगर विश्वास किसान को दिया जाता तो किसान आपके सहयोग देते। यह देश खुशहाल हो सकता है लेकिन इसके लिए आपके इनिशिएटिव लेना होगा। किसान से आपके द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। आज समझा जाता है कि किसान भालदार हैं। आज डी-हार्डिंग की बात भी की जाती है। मैं मानता हूँ कि किसानों के पास गेहूँ हो सकता है तो वह बड़े किसानों के पास हो सकता है लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही था? हमारी सरकार ने गांव में रहने वाले भूमिहीन के प्रति कोई इन्तजाम किया था? गेरा कहना है आपने उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं समझी। अगर आप जिम्मेदारी समझते हैं तो रणवीर सिंह जी के प्रति समझते हैं जिनके पास बहुत गेहूँ हो सकता है लेकिन गरीब मजदूर के प्रति नहीं।

इन शब्दों के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार से कि इन सब बातों का, इन सब समस्याओं का हल इन्क्रीज्ड प्रोडक्शन है। उसके लिए आप को किसान को इनिशिएटिव देना होगा, उसे विश्वास में लेना होगा। उसके फंडर प्राइस देनी होगी वरन् इस देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।

श्री रणवीर सिंह (हरियाणा): सभापति जी, आज चर्चा हो रही है देश में कम पैदावार की वजह से जो देश में मुश्किलें आई हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : आप अपना गेहूँ निकालें।

श्री रणवीर सिंह : मान्यवर, अभी हमारे पूर्व बक्ता ने जिक्र किया गेहूँ के बारे में वे

इस बात को भूल गए कि जब देश आजाद हुआ था और जिस सूबे के हम रहने वाले थे उस सूबे के अन्दर इतना अनाज पैदा नहीं होता था जितना वहाँ के आदिमियों के खाने की जरूरत थी। उस सूबे के अन्दर 35-40 लाख आदमी बंधर हो कर आये थे और आज सारे देश की नजर अनाज के लिए हरियाणा और पंजाब प्रदेश की तरफ जाती है, हरियाणा प्रदेश जिसका जन्म 1966 में हुआ था इसमें 1966 से इतना अनाज पैदा नहीं होता था जितना हम को जरूरत होती थी लेकिन मुझे खुशी है कि आज देश की मुश्किलों में हमारा प्रदेश और पंजाब प्रदेश जिसके हम पहलेवासी थे की तरफ अनाज के लिये देखते हैं आज वहाँ बहस नहीं की जाती है। जो आदमी बोलते बहुत हैं, बहस बहुत करते हैं वे काम कम करते हैं और यही आज देश की सबसे बड़ी मुश्किल है।

हमारे देश के अन्दर जमीन के नीचे अगर कहीं मीठा पानी है तो वह उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, बंगाल में है, असम में है। इस देश के ज्यादा यांत्रिणाओं की आवश्यकता नहीं है। इस देश के अन्दर अगर उत्तर प्रदेश के मीठे पानी का बिहार के जमीन के नीचे पड़े मीठे पानी को, असम और बंगाल के जमीन के मीठे पानी को बाहर निकाल कर प्रयोग में लाया जाए तो मैं मानता हूँ कि इस देश के अन्दर अनाज की कमी नहीं रहेगी। सभापति जी, मैं आपके बताता हूँ कि हमारे दरियाओं के पानी का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास था पानी का और जमीन के नीचे मीठा पानी नहीं था खारा पानी था लेकिन हंसले से हमारे प्रदेश ने काम किया वहाँ के काश्तकारों ने काम किया, वहाँ की सरकार ने काम किया और तेजी से काम किया। खुद खड़े हुए और देश की मदद के लिए आगे आए।

जिस बात का जिक्र अभी हमारे पूर्व बक्ता ने किया इससे पहले कि मैं उस बात की तरफ आऊँ मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि देश की तरक्की की निशानी अगर देखनी है तो चौधरी जगवीर सिंह में देखी जा सकती है। वह भी एक किसान है। हिन्दुस्तान के

[श्री रणवीर सिंह]

अन्दर 25-27 साल पहले किसान के मायने होते थे कि न उसके पास कपड़े होते थे और न जूते होते थे। और अगर उसको 3p.m. बाहर जाना होता था तो वह दूसरे लोगों के पास चीजें मांगने के लिए जाता था। चाँधरी जगवीर सिंह जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले यह स्थिति थी कि जब गांव के किसी भाई को बाहर में जाना होता था या बाहर कहीं जाना होता था वह किसी से चादर मांगता था, किसी से दूसरी चीजें मांगता था। आज यह हालत नहीं है। जमाना बदल गया है। चाँधरी जगवीर सिंह बता सकते हैं कि उनके गांव में कितने ट्रैक्टर हैं और कितने बिजली के पम्प चलते हैं।

श्री जगवीर सिंह : पम्पों के कितने घंटे बिजली मिलती है ?

श्री रणवीर सिंह : हमारी सरकार ने गांवों में खेती के सुधार के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। इस बात को देखने से पता चलता है कि हमारे देश के गांवों में पहले कितनी खेती होती थी और आज कितनी होती है ? हमारे विरोधी दल भाइयों में और हम में फर्क इतना है कि हम इस तबदीली को कबूल करते हैं लेकिन हमारे विरोधी भाई इसको कबूल नहीं करते हैं। आज हमारे देश में मुश्किल यह है कि जो भाई क्रम नहीं करते हैं वे सबसे बड़े नेता हैं और जो आदमी या प्रदेश क्रम करते हैं वे पीछे की पंक्ति में रहते हैं।

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) : एक बात मुझे यह कहनी है कि आज हालत यह है कि आज जो गवर्नमेंट बनती है उसमें किसानों के नुमायन्दे बहुत कम हैं। आज शहरों के लोग ही, जिनमें वकील आदि होते हैं, कॉन्ग्रेस बनाते हैं। इसलिए गांवों की परवाह पूरी तरह नहीं होती है।

[The Vice-Chairman (Shri Jagdish Prasad Mathur) in the Chair]

श्री रणवीर सिंह : त्यागी जी कह रहे हैं कि आज जो सरकार बनती है वह शहरों के लोग ही बनाते हैं। मैं उनकी इस बात से सहमत

हूँ लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पहले त्यागी जी भी कुछ बने थे और वे हिन्दुस्तान के फाइनेंस कमिशन के चयनमें थे। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि त्यागी जी के बाद श्री बृहमानन्द रेड्डी दूसरे वित्त आयोग के चयनमें बने थे और उस वित्त आयोग ने जो सिफारिश की थी वे सिफारिशों त्यागी जी वाले वित्त आयोग की सिफारिशों से गांव वालों के और प्रदेशों के हित में ज्यादा थीं मुझे यह मालूम नहीं कि उस वक्त त्यागी जी पर शहरों के लोग चढ़े हुए थे या वहाँ के पकलखं लोग चढ़े हुए थे। अब जब वे वहाँ से निकले तो उनका शहर वालों दिव्याई देना लग्ये।

उप-समाध्यक्ष महादय, मैं यहाँ पर प्रधान मंत्री जी का भी जिक्र करना चाहता हूँ। सन् 1966 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधान मंत्री बनी थीं तो उस वक्त बिजली से चलने वाले पम्पों की तादाद इस देश में 10 लाख से भी कम थी और आज उनकी तादाद 25 लाख से भी ऊपर है।

श्री जगवीर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये पम्प कितने घंटे चलते हैं ?

श्री रणवीर सिंह : चाँधरी साहब पूछ रहे हैं कि ये पम्प कितने घंटे चलते हैं। पहले तो इन्हें बिजली मिलती ही नहीं थी, आज ये पूछते हैं कि पम्प कितने घंटे चलते हैं। अगर हमारे ये माननीय सदस्य देहातों में जाकर बिजली की स्थिति को देखें तो मैं यह समझता हूँ कि इन लोगों को श्रीमती इंदिरा गांधी के गीत गाने चाहिए जिन्होंने इस देश के गांवों में बिजली पहुँचा दी है। पहले हमारे देश के 75 हजार गांवों में बिजली पहुँच चुकी थी, आज हिन्दुस्तान के डेढ़ लाख गांवों में बिजली पहुँचाई जा चुकी है। मैं यह मानता हूँ कि इस देश के हर गांव में बिजली जानी चाहिए और किसानों को बिजली मिलनी चाहिए। कारखाने में रात को भी काम हो सकता है, खेत में तो बिजली दिन में मिलनी चाहिए . . .

श्री जगवीर सिंह : इतना ही मनवा दीजिए बस।

श्री रणवीर सिंह : बात तो दुरुस्त है। अगर मानने से बात चलती हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ बहिन इंदिरा गांधी आपसे पहले ही कर जाएंगी . . .

SHRI G. LAKSHMANAN (Tamil Naciu): It is a State subject. How can the Prime Minister take credit for it?

श्री रणवीर सिंह : लक्ष्मणन जी, आप भूल जाते हैं आपके प्रदेश के अंदर जो तरक्की हुई है किसलिए हुई है, मेरे प्रदेश के अंदर जितनी तरक्की हुई वह किसलिए हुई है ? वह डी.एम.के. की सरकार की बिना से नहीं हुई है, हमारी सरकार के बिना से नहीं हुई है, वह हिन्दुस्तान की केंद्रीय सरकार ने रखी की सहायता दी है। आपको इस लायक किया है कि आप खड़े हुए, आपको कर्जा दिया ताकि आप कर्ण लगा सकें, आप गाइडर इरिगेशन का काम बढ़ा सकें और बिजली लगा सकें।

SHRI G. LAKSHMANAN : Can he say how much financial assistance has been given to the State Government for getting pump sets?

श्री रणवीर सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब स्पेशलफिकली आप देंगे। अगर मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा।

SHRI G. LAKSHMANAN : Can he give the information?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद साधु) : चौधरी साहब आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री रणवीर सिंह : आपने जिक्र किया था और मैं समझता हूँ उनका ऐतरज भी हुआ। बात महत्वपूर्ण है कि जो प्रदेशों की हमारी योजनाएं हैं उनके अंदर भारत की सरकार कितनी वित्तीय सहायता देती है, रखी की कितनी सहायता देती है ? क्या आप इस बात को मानते हैं कि वित्त की सहायता के बगैरे आपकी डी.एम.के. पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है या हमारा प्रदेश और पंजाब का प्रदेश आज आगे बढ़ा है ? लेकिन मैं यह जानता हूँ कि हमारे प्रदेश की सरकार को

भाखड़ा डैम की योजना के लिए पैसा मिला और इसलिए आज हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों को हम अनाज दे सकते हैं, दूसरे प्रदेशों के लिए कभी कभी बिजली भी थोड़ी बहुत दे सकते हैं। हमारे यहां भी बिजली का खर्च ज्यादा बढ़ा तो डी.एम.के. का यह ख्याल मात्र है क्योंकि मैं जानता हूँ मद्रास में एक वक्त था जब मद्रास दो प्रदेश में बांटे थे मद्रास में उनकी पार्टी बनी थी और आन्ध्र वाले भाई साफ करंगे वे कहा करते थे कि मद्रास भुखा मर जाएगा अगर वह हमारे साथ नहीं आएगा। तब डी. एम. के. के नहीं श्री कामराज मुख्य मंत्री थे। उन्होंने अपने मुख्य मंत्री पद के दौरान मद्रास जो एक डीफिशिट स्टेट था उसका एक सर्पलिस स्टेट बनाया और आपने तो यही संवा की थी . . .

SHRI G. LAKSHMANAN : For your information, Shri Kamaraj was not there. Shri Rajagopalachari was there.

श्री रणवीर सिंह : थोड़े समय के बाद ही कामराज जी मुख्यमंत्री बनार्य भये थे जिन्होंने तामिलनाडु का नक्शा बदला था . . . कि उनका एक बच्चे से हस्ता दिया। खैर, वह वक्त की बात हांती है, कभी आपके साथ भी ऐसा बनगा, वह वक्त भी आएगा जब आपको देखना पड़ेगा कि आपका मुख्य मंत्री 18 या 19 वर्ष के बच्चे से हारेंगा क्योंकि वह आने वाली नस्ल इस बात को भूल नहीं सकती है कि हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। (व्यवधान) चौधरी साहब, जाने दो क्यों कहलवाते हो मुझे बूढ़े के खिलाफ मेरे दिल में उनके लिए आदर है। मुजफ्फरनगर के चुनाव में कौन हारा था कौन जीता था, 1971 के चुनाव के वक्त ? आप इस बात को भी भूल जाइए आप कितने जीते। उसका जाने दीजिए, वह कहानी निराली है।

SHRI G. LAKSHMANAN : Prime Minister Indira Gandhi can also be defeated.

श्री रणवीर सिंह : मैं मानता हूँ कि हमारे देश के लिए यह कोई इज्जत की बात नहीं है कि हम विदेशों से अनाज मंगाएँ जब कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, हम बाहर

[श्री रणवीर सिंह]

से अनाज मंगायें, कपास मंगायें और बाहर से कोई और चीज मंगायें जिस चीज को हम अपने खेतों में पैदा कर सकते हैं। हमें अपने देश के हर चीज के लिए स्वावलम्बी बनाना चाहिए और इस बात में दौड़ें नहीं हो सकती हैं। सरकार और विरोधी दल के जो सदस्य हैं वे सब चाहते हैं कि हम हर चीज में स्वावलम्बी बन जायें। लेकिन स्वावलम्बी बनने के लिए सरकार की नीति में कुछ फर्क आने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ प्रदंशों की सरकारों और लोगों के काम करने के तरीके में भी फर्क आना चाहिए। अगर आपका इस बात की शिक्षा लेनी है, तो मैं एक बात कहता हूँ उन लोगों से जो प्रताप सिंह करों के क्रीडक हैं, जो बंसीलाल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, कि वे लोग पंजाब और हरियाणा में जाकर देखें और वहाँ से शिक्षा लें। वहाँ पर किस तरह से तरक्की हुई है और 50 मील तक नहरें एक साल के अन्दर बन गई हैं। जब देश में तेजी आयेगी तब ही काम हो सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश में कुछ तेजी आनी शुरू हो गई है और वह आगे बढ़े है। लेकिन इस तेजी के तो हमारे कुछ लोग मरने के लिए तैयारी में हैं क्योंकि वे घेराव में लग चुके हैं। मैं मानता हूँ जैसा कि उन्होंने जिक्र किया है कि घेराव की जरूरत है। अगर चौधरी रणवीर के पास था चौधरी जगवीर सिंह के पास उसकी जरूरत से ज्यादा अनाज है, अगर किसी मंत्री के पास और साहूकार के पास उसकी जरूरत से ज्यादा अनाज है, तो उसके धंशव की जरूरत है। लेकिन आज की हालत में असेम्बलियों के घेराव की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहाँ पर भी तो हमारे जैसे गरीब आदमी बैठते हैं। अगर आप और मेरे जैसे नहीं तो दूसरे गरीब होंगे। वहाँ पर भी तो गरीब आदमी बैठते हैं। तो ये लोग क्रान्ति के नाम से क्रान्ति की बात करते हैं, लेकिन देश के क्रान्ति की तरफ ले जाते नहीं हैं।

जैसा त्यागी जी ने कहा, मैं इस बात के मानता हूँ कि हमारी नीति में परिवर्तन होना चाहिए। मैं कल, परसों कपास के संबंध में बोल रहा था और उस वक्त मुझे कहा था

कि क्रीडट स्क्वीज का बहाना लेकर किसानों को परेशान किया जा रहा है और उनके माल को नहीं उठाया जा रहा है। आज देश की आर्थिक हालत खराब होने के नाम पर इस तरह की कार्यवाही की जा रही है। मैं नहीं मानता कि हमारी आर्थिक हालत खराब नहीं है, लेकिन इस बारे में हमें आपस में साँच विचार और सलाह मशवरा करना चाहिए। सब कहते हैं कि बाजार में चीजों के दाम बढ़ गये हैं और उसको कम करना चाहिए। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमको ऐसे खर्चों में कमी करनी चाहिए जिसके द्वारा देश में पैदावार नहीं बढ़ती है। जिन चीजों के द्वारा खेतों और वास्तुखानों में पैदावार बढ़ती है, उन चीजों में कोई कमी नहीं करनी चाहिए और उन चीजों के लिए पैसों में रोक नहीं लगानी चाहिए। उस रोक के माने तो अपनी तरक्की पर रोक लगा देना होगा।

मैं यह बात समझ सकता हूँ कि जो लोग स्मगलिंग का काम करते हैं, जिनके पास चोरी का धन है, उनके काले धन को पकड़ कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और सरकार की उनको पकड़ना चाहिए। उन लोगों का घेराव करके इस बात के लिए मजबूर किया जाये कि वे काले धन को सरकार के सामने लायें ताकि वह रुपया देश की तरक्की के लिये लगाया जाये। तो इस तरह के रूपयों को आप रोकें, लेकिन जो आपने क्रीडट स्क्वीज की बात कही है, उससे तो कपास की पैदावार कम हो जायेगी, सरकार उसको नहीं खरीद सकती है, तो यह एक गलत नीति है। इसके माने तो यह हुए कि जो किसान मंहनत और पसीना बहाकर कपास पैदा करता है, उसकी खरीद एयर क्रीडिशन में बैठे हुए साँदागर करेंगे और उनके अधीन इन लोगों को छोड़ दिया जायेगा। इस तरह की जो नीति है वह एक गलत नीति है और क्रीडट स्क्वीज के माने यह नहीं होना चाहिए कि गरीब किसान परेशानी में पड़े जायें। मैं यह मानता हूँ कि जो रिजर्व बैंक के बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, जो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, उनकी यह साँच हो सकती है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह के साँच में तबदीली की आवश्यकता है और उनके

दिमागों में दृढ़ता वालों की भलाई के बारे में साँच होनी चाहिये और वह साँच यही हो सकती है। देश के अंदर जो पैदावार के लिए पैसा लगता है उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए।

श्री महावीर त्यागी : 5-7 वर्ष से इस बात के लिए बसवरा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट विलेज-वाइज सर्वे कर प्लानिंग के लिए कि किरा गाँव में किस चीज की जरूरत है और उसकी बीसस पर प्लान शुरू हो। यहाँ तो प्लानिंग रूप के बंटवारे की होती है कि इतना रुपया इस पर खर्च कर दो। यह कोई साँचता नहीं कि किस क्रम पर खर्च होना है, किस गाँव में क्या बनना है। मैं कहना यह है कि अगर आप अपनी पार्टी को और गवर्नमेंट को इस बात के लिए तैयार कर दें कि वह गाँव-गाँव का सर्वे कराए कि कौन से गाँव में क्या तरक्की हो सकती है और उसके हिसाब से प्लानिंग हो तो एक वर्ष के अंदर सास किस्सा साफ हो सकता है।

श्री रणवीर सिंह : त्यागी जी, जो आपके उद्देश्य हैं उनसे मैं सहमत हूँ लेकिन जो आप कहते हैं उससे तनखाहदारों की तादाद बढ़ेगी। यहाँ सर्वे की कोई कमी नहीं है। इस देश के अंदर सर्वे बहुत हो गया है, सर्वे के बन्द कर। इस बात के आप जानते हैं, मैं भी अनजान हूँ। जाने वीजिए, हरियाणा के और पंजाब के, तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पानी मीठा है, जहाँ किसी इंजीनियर के जाने की जरूरत नहीं है, किसी तनखाहदार को तनखाह देने की जरूरत नहीं है...

श्री महावीर त्यागी : मैं यही कह रहा हूँ। सर्वे के मानी मरे यह नहीं है कि इंजीनियर भेजे जायें सर्वे के मानी यह है कि गाँव के प्रधान को चिट्ठी लिख दी जायें कि अपने-अपने गाँव में बताओ कितनी जमीन है, कितनी आवपाशी है, स्कूल कौसा है, अस्पताल कितनी दूर है। उसकी लिखी हुई चिट्ठी के ऊपर प्लान बँस कर वीजिए।

श्री रणवीर सिंह : मैं आप जितना तजुरबंकार नहीं हूँ, लेकिन एक बार आप मंत्री भी मानेंगे

81RSS/74—9

कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और इस सदन के जो तजुरबंकार सदस्य हैं वे जानते हैं कि देश की जरूरत क्या है, गाँव के सरपंच के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही सीधी सी बात है जैसा चौधरी जगवीर सिंह ने कहा, कि आज हम फँसला कर कि जो खेती की तरक्की के लिए पैसा होगा वह और चीजों के मुकाबले में ज्यादा खर्च होगा। हम 25, 30 और 40 प्रतिशत खेती पर खर्च करने का फँसला करें तो इस क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं।

माननीय गौरे जी यहाँ नहीं हैं। पिछली दफा उनके प्रदेश में 150 करोड़ रुपया लगा उन्होंने कहा 150 करोड़ रुपया लगा तथा कभी फायदा हुआ। उसके ऊपर भी शक कर रहे। यही मुश्किल है। हमारे और आप जैसे विद्वान जो लोगों के नुमाइन्दे बन कर आते हैं उनके ध्यान में टीकानिटपणी करते वक्त यही रहता है कि उनको किसी चीफ मिनिस्टर से गिला है या किसी पार्टी में मिला है, वे यह नहीं साँचते कि जो हम कह रहे हैं उसका असर क्या होगा। मुझे इतना ही निवेदन करना है कि आज देश के अन्दर जरूरत इस बात की है, जैसी कि इन्दिरा गांधी जी ने शुरूआत की है, कि माइनर इरीगेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपया दिया जायें। मैं तो यह कहता हूँ कि कोई ज्यादा बड़े तंत्र की जरूरत नहीं है एक छोटा सा मंत्री इस देश को आगे बढ़ा सकता है। जो भी कोई योजना खेती में सिंचाई बढ़ाने के लिए या खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए एक साल में पूरी की जा सकता है उसके लिए खर्च के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए।

श्री महावीर त्यागी : जरूर।

श्री रणवीर सिंह : उसके ऊपर किसी बहस की जरूरत नहीं, विशेषज्ञों की राय की ज्यादा जरूरत नहीं क्योंकि देश के लिए अनाज चाहिए।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : वही तो यह सरकार करना नहीं चाहती।

श्री रणवीर सिंह : यह सरकार तो करना चाहती है लेकिन आप लांग धराव में लगे हुए हैं। आप अपनी हार की भेंट मिटाने के लिए किसी का पर्दा उठाये फिरते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : उस तरफ नहीं, इस तरफ बोलिए।

श्री रणवीर सिंह : उपाध्यक्ष जी, मुझे उस तरफ भी बोलना पड़ता है और आपकी तरफ भी बोलना पड़ता है। मुझे याद है जब आप बोल रहे थे तो आपने क्या कहा था। मुझे इतना ही निवेदन करना है कि जैसे हरियाणा में हमने साबित कर दिया है कि एक साल की योजना एक साल के अन्दर ही खत्म हो सकती है। अगर हम 10 करोड़ रुपये की योजना आपके सामने, कृषि मंत्रालय के सामने भेजेंगे और एक साल की अवधि में उसका पूरा कर देंगे, 11 महीने में कर देंगे, 13वां महीना नहीं जाने देंगे तो उसका आपको सहायता देनी चाहिए। जो इम्तिहान में पास हो, जिस काम में आपका विश्वास है कि यह काम साल में पूरा हो सकता है तो उस परसे का कम-से-कम आप अवश्य दीजिए। चाहे कितना पैसा लगे अगर उस परसे से अनाज की पैदावार बढ़ सकती है तो उसके ऊपर कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके मंत्रालय में नहर का भी मंत्रालय आ गया, सिंचाई मंत्रालय भी है। . . . Interruption आंम मंहता जी आप कहां फंस गये, मैं पैसा मांगता हूँ, आप बीच में आ गये।

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सूधार तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री आंम मंहता) : अगर इतनी आसानी से पैसा मिलता है तो मैं चला जाता हूँ।

उप-सभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : आंम मंहता जी से झगड़ा करने पर पैसा नहीं मिलेगा।

श्री रणवीर सिंह : तो मैं निवेदन कर रहा था कि कृषि मंत्रालय के पास अब सिंचाई विभाग भी आ गया है। जवाहरलाल नेहरू प्रोजेक्ट हमारे प्रदेश के अन्दर एक योजना

बनाई है और उस योजना के जरिये हम जमुना जी का वह पानी जिसका बहन चूड़ावत जी कह रही थीं कि दरिया में जाकर बहता है वह समुद्र में बह जाता है, उस बरसात के पानी का 400 फीट उठाकर सूखे वाले खेतों में डालना चाहते हैं और उस योजना का एक साल में हम पूरा करना चाहते हैं। तो आप 10-15-20 करोड़ रुपये जितना दे सकें उतनी आप हमें छूट दें। हमारी सरकार का यह भी हौसला है कि अगर साल के आखीर में दे सकें तो हमका विश्वास दिला दें तो हम अपने हौसले पर इस काम का चालू कर देंगे। हमका इस बात का जोर नहीं है कि हमका आज ही पैसा मिले जैसे राजस्थान के अन्दर पहले पैसा दो, फिर काम होगा। जो कुछ भी हो रहा हो, उनकी मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि कई प्रदेश हैं जिनके काम करने का मंहगा तरीका है, दूरे भी लगती है। जिन प्रदेशों के अन्दर काम करने की शक्ति है और जो प्रदेश आगे बढ़ सकते हैं उनका माँका दिया जाना चाहिए। बहुत सारे भाई हैं जो मानते हैं कि कुछ इलाके बहुत पिछड़े रह जायें तो देश के अन्दर अच्छी योजना नहीं बनेंगी, उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन साथ में सबसे बड़ा ख्याल यह होना चाहिये कि देश में अनाज पैदा होना चाहिए। कहां हाँ, किस कान में हाँ, इस बात की हमें फिकर करने की आवश्यकता नहीं है। आज तो आवश्यकता यह है कि जैसी आपने परेशानी जोहिर की मैं नहीं मानता हूँ कि आज हमारे देश में कोई भूख से मर रहा है। ये भी जिस तरह से कुछ भाई हैं जो धराव खामखा करते हैं, यह भी एक नारोबाजी है। यह इस देश की इज्जत को उंचा नहीं करती, इस देश की इज्जत को गिरानी है। मैं यह मानता हूँ कि हमारे देश के अन्दर अगर कोई भूख से परेशान है, कोई तकलीफ में है तो उसकी मदद होनी चाहिए। इसीलिए मैं यह भी मानता हूँ कि बहुत सारे साँच वाले भाई यह सोचते हैं कि शहरों में राशनिंग हो और देहात का जो मजदूर है, जो हिन्दुस्तान का सबसे गरीब अंग है उसका राशनिंग की आवश्यकता नहीं, यह साँच ठीक नहीं है। यह साँच बिलकुल गलत है। मैं

समझ सकता हूँ कि हमारे जैसे भाई जगवीर सिंह जैसे भाई जो पैदा करते हैं उनका अनाज और ज्यादा ले लें, लेकिन इसके साथ-साथ यह जरूर होना चाहिए कि दुहात में जिनका खेत मजदूर रहते हैं, उनकी खरीदने की शक्ति बहुत कम है। तो राशनिंग सबसे पहले किसी के लिए होनी चाहिये तो उनके लिए होनी चाहिये। लेकिन राशनिंग आज किसके लिए होता है ?

उप-सभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) :
अब समाप्त कीजिए, हो गया।

श्री खगवीर सिंह : अभी समाप्त कर रहा हूँ। जो मंत्रालय के सचिव हैं उनके लिए भी हैं, जो सदस्यगण हैं उनके लिए भी हैं, शहर में बड़े-बड़े साहूकार हैं, करांडपीत हैं उनके लिए भी हैं, लेकिन उस गरीब के लिए राशनिंग की सोच नहीं है। यह गलत है और इसको हमें बदलना चाहिए। महापति जी में आखिर में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि भूख से हिन्दुस्तान में मरे थे आज से 30-31 साल पहले। वं हजारों की संख्या में नहीं थे जिस तरह से आज हजारों की बात की जाती है बल्कि उस वक़्त 12-23 लाख भाई अकाल से बंगाल में भूख से मरे थे जिससे दुनिया को पता लगा था कि हिन्दुस्तान में कुछ हुआ है। आज तो हिन्दुस्तान की इज्जत उंची हुई है। हिन्दुस्तान में बंगला देश तक के लोगों को भूखों नहीं मरने दिया गया इन्दिरा गांधी सरकार ने। आप किसना ही प्रचार करे दुनिया में यह यकीन नहीं आ सकता कि इन्दिरा गांधी अपने देश के किन्हे लोगों को भूख से मरने देंगी। यह अपमान बात है जो राजनीति है उस राजनीति को परे रख कर आर्थिक नीति के ऊपर अपनी विचार प्रकट करने चाहिए। मैं महसूस करता हूँ कि खेती की पैदावार के लिए हम जितना ज्यादा पैसा दें वह देश के तिन की बात है। खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए जितने सरमाया पास होने की जरूरत है उन्हें वह कपास हो, चाहे वह गूड़ हो, चाहे वह पीने हो, चाहे वह गेहूँ हो, चाहे वह चावल हो उसके लिए जितने सरमाया की जरूरत है उतनी देनी चाहिए। अगर हम

नहीं देते हैं तो हम विचालियों के हाथ में खलते हैं। विचालियों के हाथ से किसान को हमें बचाना चाहिए।

SHRI G. LAKSHMANAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Government of India does not accept that there are starvation deaths in this country for the simple reason that the Government of India believes in fate—it is the fate of a citizen to die of starvation and, therefore, he died. Sir, though we call our country a secular State, what do we do? As soon as the late Dr. Zakir Hussain became the President, he went and got the blessings of the Shankaracharya. He washed his feet and took that water. Our present President, Shri Fakhruddin AH Ahmad, as soon as he was elected President, went to the Vinayak temple and got the blessings of Vinayak. Therefore, Sir, we believe in fate. That is why, in spite of the fact that starvation deaths are taking place all over the country because of the policy of the Government with regard to food, they are not prepared to accept it and they believe in fate. They believe that it is the fate of an individual to die of starvation and therefore, he has died. That is why they do not accept there have been starvation deaths.

Sir, our country has not advanced in spite of the four Five Year Plans because we have not given importance to agriculture. 65 per cent of our river water even today, after 27 years of independence, gets into the sea. And three-fourths of our cultivable land is still very barren and is not cultivated. And how can we expect that there cannot be starvation deaths? There shall be starvation deaths. Therefore, Sir, in planning, we must give importance to agriculture. And that is why, Sir, I am reminded of a couplet in Tamil :

"Uludundu vazhvaare vazhvaar
Matrellam to/hudundu pinselvar."

That means, those who plough the land are the real people who produce wealth. And all the other people have to follow them. This is from Thirukkural. But, Sir,

[Shri G. Lakshmanan] what is the position of a peasant today in our country ? Does he get a living wage ? Is he able to make both ends meet ? No. He is not able to get it. That is why, Sir, in this country, the living conditions of the peasant have not improved. My previous speaker is not here. He said that our Prime Minister is responsible for electrifying 1,50,000 villages. Of course, there are 7 lakh villages in the country. I would like to say, Sir, if the Prime Minister is sitting in that place, it is because of the Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Karuna-nidhi and the D.M.K. Therefore, this credit. I can also take. When the Congress was split, when the official candidate for the Presidentship was contested by Mr. Giri, it was the D.M.K. which came to the rescue of the Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi, to save her from that defeat. But for the votes of the DMK, Mr. Giri would have been defeated ; that means Mrs. Indira Gandhi would have been defeated. Therefore, though we are a small Party and our Chief Minister is a small man, he took a correct decision to support the Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi, and therefore Mr. V. V. Giri. You must know that only in the second counting of votes Mr. V. V. Giri, had won, and those votes were of DMK. Had we voted against him and supported Sanjiva Reddy, which was requested to by no less a person than the greatest politician of India, Mr. Rajagopalachari, and by Mr. Kamaraj and all the other people, the Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi, would not have been the Prime Minister but somebody else would have become the Prime Minister of India, and the result would have been that in the front benches only people like M/s. Kamaraj, S. K. Patil, Atulya Ghosh and Nijalingappa would have been there, but all these people have been shunted out and only second and third rank people have become Ministers. That is also something for which DMK is responsible. Ours is a small Party.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA (Karnataka): Has it improved the efficiency of the Central Government or has it come down ? What has happened ?

SHRI G. LAKSHMANAN: Sir, my predecessor took the credit for supplying so many pump sets whereas that credit should also come to us. We have made Mrs. Indira Gandhi the Prime Minister and therefore that credit comes to us.

Sir, with regard to river water disputes, for the past 25 years no dispute has been settled by the Government of India, though we say that we are an integrated nation or an intergrated country. For instance, Sir, this Cauvery water-T-I think Mr. Lakshma-na Gowda will not oppose me—Cauvery is the only river in India where all the water is being utilised for cultivation purposes. If you go to Pumphar, you will not be able to say whether it is Cauvery itself because the entire water is being utilised by the peasants in Thanjavur district. Now a situation has arisen and the Chief Minister of Tamil Nadu has already sent a telegram and we have given a memorandum to the Food & Agriculture Minister, Mr. Jagjivan Ram, and he has said he would consider it. Now, 1,300 crores cubic ft. of water of Cauvery has been kept by the Karnataka Government and they say in the year 1972 agreement was reached between the Chief Ministers that within six months everything would be settled. They say that the period is over and therefore we need not give water to Tamil Nadu. This is here. Now, a Chief Ministers' Conference is going to be held. Why I say this is whether it is a question of water dispute or any other dispute, every State takes its own point of view only and does not approach the problem in a national way. What would happen if Cauvery water is not given to Tamil Nadu now ? Then, definitely, Sir, 7,00,000 acres of land will get dry. and now the monsoon has also failed. That will affect the granary of the South—Thanjavur district is the granary of the South— and we will have to starve and there will be starvation deaths for which, I think, the Chief Minister of Karnataka will be held responsible. The Government of India is having a meeting of the Chief Ministers. I would appeal to the hon'ble Minister Shri Shinde—Mr. Jagjivan Ram is not here—to voice the grievances of the people of Tamil Nadu. Of course,

Mr. Urs, the Chief Minister of Kar-nataka is telling the people that after the construction of the channel he would require water for his State. But we immediately need water and we have told him that you please give us water to us on loan, but they are not prepared to give. In these things, the Government of India should not have a political approach to the problem. Their party is the ruling party in Karnataka and there is a feeling in Tamil Nadu that since the Chief Minister of Karnataka is doing it, since he belongs to the Congress Party; the ruling party is the Congress Party and in the Centre also, the ruling party is the Congress Party...

THE MINISTER OF STATE IN THE I MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION, (SHRI ANNASAHIB P. SHINDE) : There would not be any political approach in these matters.

SHRI G. LAKSHMANAN : ,That is the j feeling of the people in Tamil Nadu. I have expressed the feelings of the people there. I am sure that as far as the Government of India is concerned, they would not have this approach. And I am thankful to Mr. Shinde for having assured me. This is the position with regard to Tamil Nadu.

With regard to electricity also, my predecessor was speaking so much. We have been having so many power cuts. Now 15 to 25 per cent of power cut has been given effect to from the 1st of December. We have been asking that the second mine cut in Neyveli should be taken up immediately. If it is not taken up immediately, this power cut will be there. There was a reference to pump sets. I am proud to say that as far as the pump sets are concerned, Tamil Nadu is at the top. 50 per cent of the pump sets are being supplied by Tamil Nadu only. In Tamil Nadu, except Cauvery we do not have any other source, of water. Therefore, we are utilising this thing and so many pump sets are being given. We want electricity. Electricity is not available. We have also given electricity to all the

villages in Tamil Nadu. We have given electricity to all the Harijan colonies. No Harijan colony is left cut without electrification. Therefore, we want this electricity. The second mine cut in Ney-eli should be taken up immediately by the Government of India. But if we do such things, will it be sufficient ? No, the farmers and the nation must have a scientific approach to the problems facing the country. Unless and until the farmers and the nation approach the problems in a scientific way, there cannot be any solution. We have not scientifically improved as far as our cultivation methods are concerned, like lapan and some other countries. We have not improved. Why ? We believe that land is God ; the land owner is the landlord. Our system is like that. Are we doing anything to break this system ? We are not doing anything. Take Kumbh Mela. Prime Minister of India participates in Kumbh Mela where people come without dress. If anybody goes in the street without dress, he is arrested. But in Kumbh Mela people are coming. And they call it Nirvana. Prime Minister of India goes to encourage it. How will a scientific mentality, a scientific approach come to the social system in this country ? The people who are in power, the people who are the leaders of the country, they must have a scientific approach, and the Prime Minister should not go to Kumbh Mela. She should say : "How can I go and see that ?" But by going there, she wants to tell the people that she is so God-fearing and she thus attends Kumbh Mela. And how many votes she gets from Kumbh Mela ? Nearly 50 to 60 lakhs of votes are assured. This is the approach. Therefore, a revolution has to take place, not the revolution of the type Mr. Jayprakash Narayan think of; a revolution has to be brought in, a social revolution, in which the ruling party, the Congress Party can play a role. But will they play a role ? They will not. That is why I asked why should the Prime Minister of India attend Kumbh Mela. Unless and until this social system is completely revolutionised in this country on a rational basis, any revolution, any reform that you

[Shri G. Lakshmanan] may bring in, will not have any effect. Therefore, Sir, I say that the Government of India should approach this problem in a scientific way. That is what the Prime Minister Pandit Nehru taught the world. He wanted a scientific approach to the problems. Of course, he also went to attend Kumbha Mela. That is for votes purposes. These superstitions are to be removed when we say that landlord is the lord because he was good pious man in his last birth and because the other person was a sinner in his last *janama*, he has become the farmer. With this feeling, the farmers in our part do their work. This must be completely revolutionised. If I put my efforts, if I rut my labour. I should also become like the other man. That is why he is your landlord and you are a land tiller. These things must be completely removed from this country. The ruling party says it is a secular State. What secularism is it ? The secularism is, as I mentioned just now, Dr. Zakir Husain, after he becomes the President of India, goes and washes the feet of Shankaracharya and takes that water. Is it secularism ? Will we improve this country or any country which has attained independence ? China was very backward. Let us go and see it today. It does not mean that I accept the system of government there. They have revolutionised their country. They have revolutionised their people, their mental makeup and that is how they are going forward. Therefore, a social revolution is necessary now in this country to accelerate economic revolution. With these words, I thank you for the opportunity given to me to speak.

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, Sir, more than one hundred and twenty-five years ago Karl Marx said that a spectre was haunting Europe. I say now a spectre is haunting India, the spectre of famine. The megalomaniacs, missionaries of death and almost the paid servants of monopolists, land lords, profligate, black money big traders and speculators are ruling at the Centre and on this Government squa-

rely lies the responsibility for bringing the country to the verge of the abyss. Famine has become an in-built feature of our country today. Now, I heard it in the other House and I have seen Press report and they say no one has died of starvation. Shri Jagjivan Ram says no one will be allowed to die of starvation. If they blindly say so, I say what more cruel joke could be played upon the people of India. What blatant lies could be peddled on the floor of Parliament ? Perhaps they are disciples of Shankara-charya and believe in Maya. They are saving to the people who have died of starvation: Ye, who have died, listen to us. You have not died of starvation. You were wellfed and wellhoused and if you have died that is your fault. Unfortunately, perhaps the dead souls do not hear. Now, Sir, in passing I will only say that the President of West Bengal Congress, Shri Arun Maitra, almost two and a half months back said that in one district of West Bengal more than 1,000 people have died of starvation.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : Mr. Niren Ghosh, I give you a factual information. I have received a telegram from him saying that the statement which is attributed to him is not correct. Please do not base your arguments on that.

SHRI NIREN GHOSH : Then, you have pressurised him.'

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE : It is very unfair.

SHRI NIREN GHOSH : Two and a half months back it appeared in the Press said you did not think it fit to contradict it. Now you say you have got a telegram. Wonderful. Who will believe You. None will believe it.

Now, let me come to the other points. According to reliable reports and estimates, more than one-third of the total population of India is affected by famine and starvation. The worst affected areas

and States are : West Bengal—12 out of 16 districts ; Assam, particularly Goalpara District; Gajarat—particularly Kutch and Saurashtra wherein 17 out of 19 districts are the worst affected and 15 million people are starving; in North Bihar where half the population of the State lives, nine out of ten districts are severely affected and according to the Government's own admission, 550 people have already died of starvation in Kerala. Is it also a maya, an illusion ? In Orissa, at least ten million people are under starvation. About two months ago, Sardar Swaran Singh, the then Foreign Minister, said in Washington that not a single man had died of starvation in India, that the American papers had been exaggerating the depth of famine condition, etc. What is the use ? It is no use hiding the truth. It is very patent to the naked eye. Later, the Prime Minister also referred to this and also told the same thing at the press conference in New Delhi. But on October 20, 1974, the Agriculture Minister, Shri Jagjivan Ram, declared that "I have already said that nobody will be allowed to die of hunger". In replying to the last debate on starvation in the other House, Shri Jagjivan Ram emphatically refused to admit the fact that people have died and are dying of starvation. Very recently, the Prime Minister has coined a new formulation on the causes of food scarcity in India. According to her, the Bangla Desh conflict in 1971 is mainly responsible for the crisis. It was in 1971. Now we are in 1974. Three years, 1972, 1973, 1974, have gone.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : What are you reading from ?

SHRI NIREN GHOSH : These are my notes. I collect these materials from your reports, Press clippings and all that.

So, I am bound to say that it is like the Roman proverb that when Rome was burning Nero was fiddling. The Official and Press reports are of no importance to the ruling Party. It is not

accidental that the Washington Post of the USA, in a write-up dated October 27, had observed :—

"With Mrs. Gandhi's popularity at its lowest level in recent years, the Government has ordered newspaper editors to keep famine stories and photographs off their front pages."

The New York Times dated 27th October had said that :—

"anguished scenes are unfolding in the northern and the eastern India and famished children are digging grass, bark or roots to stay alive."

The Far Eastern Economic Review of Hong Kong, dated November 15, 1974 writes :—

"India is trying its utmost to soft-pedal reports of famine in some parts of the country. New Delhi has sent strict instructions to the diplomatic missions abroad that they should blindly deny stories in the international Press saying that the problem is reaching serious proportions."

"Envoys are required to tell foreign officials that the situation has been exaggerated in the media".

Sir, the American Times dated 15-11-74 writes :—

"Henry Kissinger also discussed the question of food aid to India."

Mrs. Gandhi refuses to acknowledge publicly that thousands of people died of starvation in the States of Bihar and West Bengal. The Prime Minister having proudly proclaimed her country's self-sufficiency after a record harvest in 1971 "was reluctant to accept any aid that made India seem to be on the American dole again". Henry Kissinger nevertheless negotiated agreement which will provide 5 lakh to 1 million tonnes of grains at inexpensive prices on a long-term deferred payment basis. Not only that, according to information gathered from reliable sources import of food at concessional rates, PL 480, aid through backdoor, on government-to-government

[Shri Niren Ghosh]

basis arrangements are on the way to ! finalise the import of about 10 million j tonnes through U.S. Multivational Corporation. I accuse the government. That is why this hush hush policy.

SHRI JAGJIVAN RAM : From which report you are quoting ?

SHRI NIREN GHOSH : From a reliable source. This is inside information of your government. I am not bound to disclose the source from which I get inside information of your government.

SHRI JAGJIVAN RAM: Will you please send that chit to me ?

SHRI NIREN GHOSH : Those who are party to this private discussion tell us. So it was the subject-matter of a discussion between Indiraji and Henry Kissinger. This is a serious accusation that I am making with full responsibility. How many crores will you spend ? Hundreds of crores of rupees to import food. You say it is secret information. And you said the other day that it is not in the public interest to disclose anything.

SHRI JAGJIVAN RAM : If you cannot disclose in public interest how can we disclose ?

SHRI NIREN GHOSH : All these years it was in the public interest to say so. Now that you are in fishy business entering into secret deals you are saying so.

Sir, the scarcity is man-made. According to Government's own admission the scarcity is only marginal. In reply to a question in the other House a few days ago, the Government gave the following figures.

In 1972-73, total production of cereals was 87.1 million tonnes, and the total import 6.97 lakh tonnes. In 1973-74, total production and total import were 93.9 million tonnes and 43.47 lakh tonnes respectively.

Per capita daily (average) availability of cereals, (as per Economic Survey 1973-74)

in 1973 was about 350 grammes. In 1974, this availability must have gone up to more than 400 grammes per day, or more than 2,800 grammes per week.

In the statutory rationing areas, which do not cover more than 10 per cent of the total population, supply of cereals per week per card comes to less than 1800 grammes. Modified rationing scheme has become a paper scheme. Here the usual supply is 500 grammes per head per week and that too is irregular. The scheme does not simply exist. It has broken down. Where the rest have gone ? Why this acute crisis and famine condition ? Let the Government reply.

Take the case of West Bengal. Their paper 'Jugantar', belonging to their Minister, Mr. Tarun Kanti Ghosh recently wrote the following :

"This year the output of paddy-cum-rice and wheat in the State was not too small. .."

"Enough paddy-cum-rice was grown in the State to provide foodgrains at the ratio of 1602 grammes per capita per day. The shortfall caused by drought, flood, etc. is met from Central Pool. The Centre is providing about 1.6 million tonnes. Why then is there such a huge shortage of foodgrains ? Procurement may not have been up to the expectations. But where has the State's output of paddy and rice gone ?" This is a vital question. "Some say about 1 million tonnes of rice are still being secretly held by the hoarders and big farmers, and the Govt, has adopted a programme of dehoarding 1 lakh tonnes from this hoard. But is it now possible to dehoard this rice ?" The Yuva Congress or the Youth Congress dehoard from the I-CI godowns and then take it back to the FCI godowns. A wonderful sort of de-hoarding that the Indira Youth Congress is doing!

Out of a total production of nearly 6 million tonnes of rice in West Bengal and a marketable surplus of about 1.5 million tonnes, the State Government had decided to procure only 5 lakh tonnes. And

they procured only 1,60,000 tonnes. This was inevitable as the Government was depending on the "goodwill of the rice mill owners while the big farmers were depending on the Government's unwillingness and incapacity to hurt them". Thus only about 40,000 tonnes were procured from the rice mills against a target of 3,60,000 tonnes. The State Government has occasionally talked of using the DIR, MISA, Essential Commodities Act, etc., to unearth and seize hoarded stocks ; but nothing has been done; not a single finger has been raised in this matter. Similar is the picture in almost all the States. According to the All India Food-grains Dealers' Association, more than 3 million tonnes of wheat have been cornered by the big producers in the wheat growing States. But the Association has not said that the traders are holding 10 million tonnes of foodgrains. This Government is very soft to them. This Government does not touch them. They have pumped Rs. 1,000 crores by increasing the foodgrain price at the official level. Exorbitant prices are being charged. When the harvesting is on, rice is being sold in Calcutta at Rs. 5 per kilo. So, another round of famine is round the corner. This dehoarding has been a farce. The Government has surrendered to the vested interests. The takeover of wholesale trade in foodgrains was a farce. The next day there was a wholesale reversal and surrender to the vested interests. The price has been increased. This is the state of affairs. They are like paid servants. They have taken black money for the elections. How can they hurt them ? They cannot. They are servants of these one or two per cent vested interests.

The "Economic and Political Weekly", Bombay, dated 5th October 1974 writes under the caption "West Bengal—1943 | Being Re-enacted" : "Hunger and death are stalking vast parts of West Bengal today. The State's Relief Minister himself put the figure of starving population at 15 million. Spokesmen of the established political parties, including Ministers of the Congress, speak of starvation deaths by hundreds. Despite the Government's

attempt to seal off Calcutta from the onslaught of the hungry villagers, the city's pavements and parks are cluttered with destitute families who have managed to sneak through the police vigilance. Hunger, of course, is a perennial experience with most people in rural West Bengal. But it has not been experienced on the present scale for 31 years, not since the terrible days of the autumn of 1943."

4.00 p.m.

Under the caption "Famine in West Bengal", Economic Times, dated 18-9-1974, editorially comments : "The spectre of the 1943 famine which had taken a toll of three million lives stalks West Bengal again; Calcutta streets are crowded with famished people picking crumbs of food from garbage. Whatever euphemism the State Government might prefer, the stark reality can no longer be ignored... More than one-third of the State's 45 million people are facing starvation. This time too the famine is partly man-made. Apart from nature's havoc, mismanagement of the economy and political ineptitude have led to a situation which could possibly have been prevented... There is obviously enough food in the country-side conveniently hoarded. And yet no serious dehoarding effort has been made".

According to various estimates, starvation deaths in West Bengal vary from 15,000 to 25,000. Cooch Bihar, Bankura, Punilia, Sundarbans etc. are worst affected...

SHRI MAHAVIR TYAGI : Within how many months ?

SHRI NIREN GHOSH : Within the last four months. According to Jalpaiguri Congress, 500 starvation deaths were there in that district alone. In Sundarbans also there were 100 deaths. The number of starvation deaths in Cooch Bihar can only be guessed. A prominent journalist who recently visited the affected areas in Cooch Bihar writes the following in the Times of India :

SHRI MAHAVIR TYAGI : I hope the Minister, while replying, will either clarify or contradict these figure*.

SHRI NIREN GHOSH: He will contradict.

This journalist writes :

"As I entered Cooch Bihar town last week, I was accosted by a man...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): Is he Shri Niren Ghosh?

SHRI NIREN GHOSH:... who implored me for help in cremating a boy, all skin and bone. I soon learnt that such cases are only too common. Often bodies of victims are abandoned on the roadside, at railway stations, in school verandahs, BDOs' offices, village markets and even in the backyards of the private houses. At the present rate, they will soon stop counting the dead and official records will show nothing even to suggest that there was a disaster... The authorities have thought it necessary to organise official squads to dispose of bodies, often in batches."

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI JAGJIVAN RAM) : How many did he see himself?

SHRI NIREN GHOSH : This journalist has visited the scene. Our Party exists there. Unfortunately for you, our Party still exists in all districts of West Bengal. This is from a journalist. He went there. This is his personal report. He visited the town and toured the entire district. The West Bengal Government did not think fit to contradict this.

The Economic and Political Weekly dated October 5, 1974, writes:

In the face of such colossal distress, the State, Government has done little besides bustle around. Apart from frequent trips to Delhi by the Chief Minis-

ter and his Cabinet colleagues with a view to...

SHRI KOTA PUNNAIAH (Andhra Pradesh) : Wherefrom he is quoting?

SHRI NIREN GHOSH: Times of India.

SHRI OM MEHTA : It is all fiction by Shri Niren Ghosh.

SHRI NIREN GHOSH : It is Maya as Shankara said. Mr. Om Mehta, you live in air-conditioned rooms and enjoy saucy dishes. You cannot think of these. Some years ago, you used to think of these Mr. Om Mehta. You talked about this years and years ago with somebody whom I do not want to mention.

Now you have become a Minister and so you are talking in this vein. But I challenge : You accompany me and we will tour the portions and the areas I have mentioned and let us see the position. Are you ready ? I throw this challenge to you. If you dare, you accept this challenge

Sir, in Assam, the total number of deaths is not less than 15,000. The public-distribution system has gone ! The buffer stock in 1972 was 9 million tonnes. But in 1974 it has come down to 2.5 million tonnes! (*Time Bell*). Within two or three minutes, I will finish. Sir, I have almost come to the end of my speech.

Sir, I wanted to substantiate my point by quoting facts and figures and did not want to speak just with emotion. How can this otherwise be substantiated? I have to mention here that about a hundred Congress MLAs have not paid their levies! And, Sir, how has this levy been fixed? One has to pay about twenty quintals. But these people have influenced the BDOs and, therefore, the levy has been fixed at just two quintals and even this small levy has not been paid by about a hundred Congress MLAs of my State! This is how the Congress is behaving. Then, Sir, about 70 per cent of the irrigation has gone waste. This is according to an economic survey conducted

recently. Only a microscopic section of the affluent and big landlords and rich peasants has drawn water from the irrigation sources and 70 per cent of the irrigation has gone waste and this is also according to the same economic survey recently made by an expert committee appointed by them. Therefore, Sir, I demand that the State of West Bengal should be declared a famine-stricken State; it should be declared a famine State. Sir, nowadays they never declare a State as a famine-stricken State. They simply say that it is a scarcely-affected State and they never utter the word 'famine' because the Famine Code enjoins upon the Government certain responsibilities which they are not prepared to discharge. So, I demand that all those areas that I have mentioned should be declared as famine-stricken areas. It is the responsibility of the Government to see that these areas are taken care of properly. Otherwise, how can you call yourself a progressive Government?

SHRI ANNASHEB P. SHINDE: Mr. Niren Ghosh, what is the crop condition there?

, SHRI NIREN GHOSH: I am prepared to answer your question if you give me more time.

SHRI JAGJIWAN RAM : No.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI J. J. MATHUR): No, please.

SHRI NIREN GHOSH: I am prepared to answer everything point by point. Otherwise, if you do not give me more time, I will sit down.

Sir, I was demanding that all these areas should be declared as famine-stricken areas and the Government should discharge its responsibilities properly. Sir, I think the situation can be met if whatever production is there, if the entire surplus stocks with people having ten acres and more of wet land and 30 acres of dry land, if all these are commandeered even at the rate fixed by the Govt., that is, Rs. 74/- or Rs. 76/- per quintal. I should

also say that distress sales are going on and some bonus should be paid to these people who are making the distress sales because it is the poor and medium peasants who make the distress sales at very low prices. I know of what happened last year. According to the report from which I have quoted the other things, last year the police hunted the market during the first few days of the harvest when the poor and medium peasants came to the market and took away their stocks. Therefore, Sir, if what I have said is done, I am sure that with the rationing in a modified form foodgrains can be provided at Re. 1/- per kilo to the people. This can be done if my proposal is accepted and acted upon.

Now, Sir, these famine-stricken areas and the other areas have not sufficient funds and they speak of lack of finance, in this connection, with regard to the recommendation of the Sixth Finance Commission, I make this proposal that 75 per cent of the Central revenues in each financial year should be set apart and allocated to the States as finance from the Central pool.

The Centre can only disburse 25 per cent. Since the States have been left high and dry, then you talk of States lacking finance. Why not cut down the defence budget to half—from two thousand crores of rupees to one thousand crores of rupees? Why don't you do that? No. You will never give land, to the landless. You will never do that. You will cheat them... (*Interruptions*). Whatever authoritative reports have so far been, nothing has been done. Forty per cent of the land is concentrated . . . (*Interruptions*). Now, if I talk of China, they will think it is blasphemy. But they are 80 crores. We are 55 crores. They were far more backward and far more poverty-stricken. But nobody says that 800 million people of China cannot get a square meal. They cannot get luxurious rich dishes, but nutritious dishes are available to all. Why is India in this position? Why is there a perpetual famine in this country? Except for a year or two, each year there are

[Shri Niren Ghosh.]

starvation deaths. As I said, famine is a built-in feature of our country. I say that a government which cannot feed and clothe the people has no right to exist. Further you are a minority government. You have got only 43 and 44 per cent of the votes. You cannot speak in the name of the people . . .

SHRI JAGJIVAN RAM: You can .
(Interruptions)

SHRI NJREN GHOSH: I do not claim that I speak on behalf of all. I am humble enough. But you are arrogant . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): Please conclude .

SHRI NIREN GHOSH: I am concluding. You are making politics out of starvation by doling out assistance here and there and making the people dependent on you. You are making politics out of the deaths of the people . . . (Interruptions). But let me tell you. Leaders may come and go we will go, I will go, you will go, but hunger in India under your dispensation will remain. And I echo of the words of Nehru here, whom you call your leader—he is not my leader—who said: Hunger is the drill sergeant of the people. This hunger will remain. You may go on making politics out of it, but hunger will remain. Hunger is the drill sergeant of the people and the retribution will fall on you, and then you will know what is what.

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY (West Bengal): Mr. Deputy Chairman. Sir, I had no intention to participate in this discussion, but hearing my colleague from the same State from which I come, I am compelled to contradict him on many counts.

First of all, I do not deny that my State, West Bengal, suffers from an acute scarcity and acute drought. Consecutively for three years, we have been having droughts, and the State Government is trying its best, with the help of the Government of India, to combat that natural

calamity. Not only with the help of the Government of India, but with the help of non-official agencies also, the State Government is trying to help the distressed people. It is highly exaggerated to say that 15000 to 25000 persons have died of starvation. I challenge Mr. Niren Ghosh...

SHRI NIREN GHOSH: I also challenge . . . (Interruptions). I have thrown a challenge. (Interruptions)

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Mr. Niren Ghosh, I never interrupted you when you spoke . . . (Interruptions)

Mr. Deputy Chairman, Sir, Mr. Niren Ghosh's party has no chance to come back to this august House. So this is the last time that he will be speaking in this House from those benches . . .

SHRI VISHWANATHA MENON (Kerala): You have rigged the elections.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Wherever you have won, it was a fair and clean election held under the aegis of the Government of India

SHRI NIREN GHOSH: You have sufficient expertise in rigging elections.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Mr. Niren Ghosh, you spoke for half an hour. You should let me speak now. He was telling about M.L.As. belonging to my party not discharging their obligations and duties so far as levy and procurement are concerned. May I remind this august House that when Mr. Niren Ghosh's party was in the Government, what did they do about procurement? May I tell this august House that even today if you go to the rural areas, you will find Mr. Niren Ghosh's party telling people not to hand over their stocks to the Government? Sir, it is very easy to come here and say that my party has failed. Yes, my party has certainly failed to take appropriate steps to mop up all the surpluses. But it is not due to our Government machinery alone. They could have tackled the situation. (Interruptions) Please stop this running commentary. You should have the courtesy to listen to others. I listened to you for half

an hour patiently. Mr. Deputy Chairman, Sir, a responsible opposition always remembers how to oppose because they know that they are the alternative who may sit in the Treasury Benches next time. But Mr. Niren Ghosh's party is a desperate party which knows that never in their life they will come back to power. That is why, they are so wild in their allegations. That is why they are so irresponsible about their behaviour in the rural areas when they ask the people not to hand over their surplus grains to the Government. (*Interruptions*). The State Government of West Bengal did its best to procure as much quantity of foodgrains as possible, not only by mopping up the distress sale but also by levy and by procurement. We are responsible for some failures also. That is why we are plugging every loophole so that in future there is no such failure in procurement. Will Mr. Niren Ghosh extend his party's and his own co-operation in this? He will never do that. He and his party will politicalise the whole thing and they will take advantage of this distress.

SHRI NIREN GHOSH : We offered co-operation. But the hands of co-operation were shunned.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY : I will remind you and through you to this House that even yesterday, a Youth Congress boy was killed by their associates in Durgapur. This is the condition. Even yesterday, a bright young man was killed by their supporters in Durgapur.

SHRI NIREN GHOSH : All the killings are taking place because of your people.

SHRI WATT PURABI v MUKHOPADHYAY : Mr. Deputy Chairman, Sir, from the Government side, we arranged hundreds of gruel kitchens. Can Mr. Niren Ghosh say that anywhere any effort was made by him or by his party to provide even a morsel of food for the distressed and downtrodden people? Nowhere. We organised gruel kitchens in hundreds because we would not allow anybody to die due to starvation. He comes forward with certain reports. I want to know what was he

and his party doing to remove this distress? Nothing. It is very easy to come here and denounce the Government here and in the State. When it comes to actual practice, it is his party which came down over the small agriculturist for whom he is shedding tears and the landless labours, but when they were in Government, they did maximum damage to the lowest of the low, to the poorest of the poor. This is what he and his party stand for. About the subject before us for discussion alone scarcity, I do not deny that there is acute scarcity in my State. It is no use only giving a lecture over that. It is a question of implementing the schemes not only for relief but for prevention also so that it is never repeated again. We are trying our best to get help from the Government of India in our small & major irrigation schemes. We are also trying our best for equal distribution, at least, to the poorest of the poor. But Shri Niren Ghosh's Party are there and creating difficulties for us to function. This is his love and affection for the people. And this is how they are trying to politicalise the whole issue. I object to this Sir, I also try to draw the attention of the Government of India to the need of my State. Yes, of course, the Government of India came forward to help us. And with the help of the Government of India, the State Government could tide over the distress. I congratulate the Government of India, specially the Food Ministry, the present Food Minister and Agriculture Minister for the help we got and still are getting from them. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister will reply now.

SHRI GUNANAND THAKUR (Bihar): Sir, just a few minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : May be, this time I will allow you five minutes. But it must be known that either your name comes through the Whip or there must be some order because I cannot allow one list from the Whip and then again allow the individual Members who are getting up.

SHRI GUNANAND THAKUR: Sir, I had requested the Whip already.

उप-सभापति महोदय, चूँकि बहुत इस पर बहस हो चुकी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इतने कम समय में सम्पूर्ण देश की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा करूँ, लेकिन मैं अपने आदर्शनीय खाद्य मंत्री जी से जरूर प्रार्थना करूँगा और इनका ध्यान बिहार के सूखा और बाढ़ग्रस्त इलाकों की ओर खींचना चाहूँगा।

उप-सभापति जी, माननीय खाद्य मंत्री जी ने विपत्तियों के समय, बाढ़ के समय स्वयं उत्तर बिहार का निरीक्षण किया था। वह पूर्णिया गये थे, दरभंगा गये थे, पटना गये थे और कई जगह गये थे और मुझे भी करीब डेढ़ महीना घूमने का मौका मिला है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में और जो वहाँ का दृश्य है, उस संबंध में अधिक नहीं कहूँगा लेकिन इतनी जरूर मैं अपने आदर्शनीय खाद्य मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा और कहूँगा कि अगर समय रहते मुस्तैदी से काम नहीं लिया गया तो बिहार में हजारों लोग भूख से मर जायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं 14 तारीख के आर्यावर्त का उदाहरण देना चाहता हूँ जहाँ फ्रंट पंज पर यह अंश आता है—उत्तर बिहार में अन्नाभाव के कारण घोर दुर्भिक्ष की स्थिति। किसान मजदूर शहरों की ओर भाग रहे हैं।

आज जो स्थिति हो गई है, चाहे वह कांसी नदी की बाढ़ हो, चाहे कमला नदी की, चाहे गंडक की बाढ़ हो, उत्तर बिहार एक वीरान जैसा लग रहा है। और भूमिहीन गरीबों, किसानों और मजदूरों का कोई काम नहीं मिल पा रहा है जिसके चलते जो आगामी फसल थी उसमें काम मिला नहीं। रबी की फसल के लिए केन्द्र ने 97 हजार क्विंटल बीज दिया और मैं सीड्स कारपोरेशन से थोड़ा संबंधित भी हूँ, मैं बाढ़ जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहूँगा।

हम लोग 15-16 के पटना में थे। मुझे को पता चला कि बलाकों में किसानों का अभी तक सीड्स नहीं मिला है। रबी का टाइम आ गया है। अगर किसान को हम सीड्स नहीं देते हैं तो रबी का भी समय निकल जाएगा। जो सीड्स कारपोरेशन के डीलर्स हैं उनका यह

कहना है कि हम क्या कर सकते हैं बीज तो सरकार ने ले लिए और सरकार के माध्यम से ही वह बाँटे जाएंगे। वहाँ से भी वह ठीक ढंग से मिल पाएंगे या नहीं मुझे इसमें भी डर है।

उत्तर बिहार की बात मैं करता हूँ जहाँ बाढ़ जी स्वयं देख कर आए हैं। उत्तर बिहार के सहरसा, पूर्णिया, सीतागढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुपानी के जो इलाके हैं उनकी हालत बड़ी दुःखनीय है। इस संबंध में मैं चाहूँगा कि केन्द्रीय सरकार कुछ विशेष रूप से ध्यान दे। अभी हाल में जो 11 करांडे रुपये की बीज बांटने के लिए केन्द्र ने दिया है इस बात के लिए उनको निगरानी रखनी चाहिए कि वह पैसा बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो और वह भूमिहीनों को ही दिया जा सके।

मैं एक बात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ वह यह है कि जब तक लेट टू दी डीलर्स, जमीन जातें को नहीं मिलेंगी तब तक वह जमीन से मोहूक्त नहीं रखेंगे। बड़े लोगों को, बड़े जमींदारों को, बड़े भूपतों को बंगामी कच्चा किये हुए है। अगर सैंकड़ों एकड़ जमीन में से 50 एकड़ जमीन नहीं उपजेंगी तो उनको कोई चिन्ता नहीं होगी। लेकिन छोटे-छोटे किसान, भूमिहीन किसान महसूस हो जाते हैं।

अभी नीरंन घांघ जी कह रहे थे बंगाल में भूख से लोग मरे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब अंग्रेजों की हुकूमत थी बंगाल में लाखों लोग मर गए थे और उस समय 16 रुपये का एक रोए, 20 रुपये का एक रोए चावल मिलता था। आज हमें इस बात का गर्व है, फसल है कि इस हुकूमत में दो रुपये किलो भी चावल हुआ, 3 रुपये किलो भी चावल हुआ लेकिन इन्सान भूख से नहीं मरा। इस बात के लिए हम यह भी कहेंगे कि पता नहीं बाढ़ जी के चरण में क्या लिखा है। जिस विभाग में वे जाते हैं प्रकृति उनकी मदद करती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम यह चाहते हैं विरोधी दल अपना सहयोग इगमेंट दें। यह खाद्य समस्या कोई दल की समस्या नहीं है यह समस्या हमारी, आपकी सबकी है। इस

हमको, आपको मिलकर हल करना है। दलगत भावना से ऊपर उठ कर इसको हल करना है। मैं चाहूंगा कि अगर खाद्य समस्या को हल करना है तो लैंड टू दी डीलर्स का भी नारा देना चाहिये और उसके लिए हमें प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि इम्प्लीमेंट हो सके। बहुत से राज्यों में 20-20 साल से कानून बन चुके हैं लेकिन गरीबों को जमीन नहीं मिल पा रही है। यहां तक कि भूदान की हुई जमीन भी, यानी जिसका लोगों ने दान किया है, जिसका बहुत खराब जमीन कह कर दान किया है वह भी जमीन गरीबों के कब्जे में नहीं हाने दी गई है।

यह अच्छा ही हुआ कि कृषि सिंचाई और खाद एक जगह कर दिया गया है। इससे रबी की फसल ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हो जाएगी। मैं चाहूंगा इसके लिए आप जरूर अधिक से अधिक बीज और सिंचाई की व्यवस्था करें। मैं प्रार्थना करूंगा कि जो बड़ी-बड़ी देश की जो योजनाएं चली हुई हैं, जैसे कांजी योजना; उसकी छानबीन हानी चाहिए। कितना नैट उससे हमने प्रॉफिट हुआ है और कितनी जमीन का हमारा टर्गेट है और कितना इन्वैस्टमेंट हुआ है। सिर्फ यह ही हाना चाहिए कि हम खपता देते जाएं और इन्वैस्टमेंट होता जाए और आउटपुट कुछ न हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि देश में जो परिस्थिति गंभीर है जैसे बंगाल में, असम में गैवा और भागों में उसका तो हमें ठीक करना है। रबी का समय आ गया है इसलिए हम सब लोगों को एक जट्टा हो कर काम करना चाहिए और सरकार को चाहिए कि गरीबों के लिए छोटे-छोटे किसानों के लिए अधिक से अधिक बीज और खाद की और सिंचाई की व्यवस्था करें। उत्तर बिहार से जो लोग छोड़कर भाग आ रहे हैं उन लोगों के लिए अधिक से अधिक हर प्रकार की सौवधाएं। उनके लिए कोई योजना बनाई जाए। मैं प्रार्थना करूंगा कि जो इलाके बाढ़ से पीड़ित हैं पिछले कई वर्षों से तटबंधों के बीच में लगभग 5 लाख किसान घिरे पड़े हैं ऐसे लोगों के लिए शिक्षा माफ हानी चाहिए।

लगान वहां पर माफ हानी चाहिए। मैं यह भी चाहूंगा कि वहां पर जो रिलीफ की व्यवस्था

की गई थी वह मुश्किल से एक महीने के लिए भी नहीं मिली। मैं वहां पर घूमकर और दौरा करके आया हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इन सारी बातों की छानबीन करें। बिहार के अखबारों के अन्दर यह खबरें भी छप रही हैं कि वहां पर चार और पांच लाख टन अनाज बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पड़ा हुआ है और वह उठाया नहीं जा रहा है। आज इस सिंचित की बला में यह स्थिति अच्छी नहीं है। बाबू जगजीवन राम जी खुद ही बिहार की स्थिति का देख कर आए हैं। मंत्री यह निवेदन है कि बिहार की गरीब, भिरीह और पीड़ित जनता का बचाने के लिए जीघ व्यवस्था की जानी चाहिए और रबी की फसल को इस प्रकार से सफल बनाया जाना चाहिए ताकि हम अपने देश की कमी की स्थिति को समाप्त कर सकें।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम): उप-सभापति जी, सदस्यों ने इस संबंध में जो चिन्ता प्रकट की है, मैं मानता हूँ कि यह स्थिति ऐसी है जो चिन्ता का विषय बन सकती है। लेकिन जब श्री गीरेन प्रॉप ने कहा कि अब बंगाल का फॉर्मन एरिया घटित करा तां मुझे ऐसा लगा कि बंगाल की स्थिति की उनका बिल्कुल जानकारी नहीं है। यह इसलिए कि बंगाल में धान की फसल इस साल इतनी अच्छी है कि अगर यह कहा जाय कि वह देश में सब जगह से अच्छी है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी और खर्रा की बात यह है कि . . .

SHRI NIRI-N GHOSH: Why is rice being sold at Rs. 5 a kilo?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please have patience to hear the Minister.

श्री जगजीवन राम: वहां पर धान की कटाई आरम्भ हो गई है और चावल बाजार में आने लगा है और मंत्री को इस बात की जानकारी होगी कि चावल के दाम में जो गिरावट आई है उस स्थिति में फिर वह यह कहें कि बंगाल का अकालघस्त प्रॉपित करा तां यह कोई समझदारी की बात होगी, ऐसा मैं अनुभव नहीं करता।

उप-सभापति जी, इन्होंने कुछ आंकड़े बताये हैं। मैं उनका दाहराना नहीं चाहता हूँ। जब कभी प्राकृतिक प्रकोप हो जाय, बाढ़ की वजह से हमारी फसल नष्ट हो जाय या वर्षा के अभाव में फसल नष्ट हो जाय या अन्य कोई भी विपत्ति आती है तो उसके कारण सबसे पहले उन लोगों को परेशान होना पड़ता है जो समाज के गरीब वर्ग के लोग हैं। उसमें सभी विरादरी के लोग आते हैं। कोई ऐसी जाति नहीं है जो कह दे कि उसके अन्दर गरीब लोग नहीं हैं। इसलिए यह प्रश्न गरीबों का प्रश्न बन जाता है। वैसे परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए दो तीन ही रास्ते हैं और अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के अधिकांश बुद्धिजीवी लोग हैं वे समस्या की जड़ में जाते ही नहीं हैं। इसका कारण यह भी है कि वे लोग विदेशों में प्रकाशित पुस्तकें पढ़कर अपने नियम बनाते हैं। उप-सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अन्न का भंडार पड़ा हो और किसी व्यक्ति के पास उस खरीदने के लिए पैसा न हो तो ऐसी स्थिति में अन्न की कमी से या भूख से आदमी मरा है, पैसा कहा जा सकता है? अथवा स्मरण होगा, मने 1967 में जब ऐसे ही स्थिति थी तो विमोदारी गंगे ऊपर आई थी। मुझे अपने आपको कुछ बधाई देनी होगी, अगर मैं यह कहूँ कि दुनिया के लोगों ने इस बात को कबूल किया कि हिन्दुस्तान ने इतनी भयंकर स्थिति को बहुत सफलतापूर्वक निभाया है। आज की स्थिति मने 1967 की स्थिति से अधिक भयंकर नहीं है और इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस स्थिति का सफलता के साथ मुकाबला किया जा रहा है।

उस समय भी मैंने उस वक्त के जो हमारे खास के सचिव थे, और आजकल वे बंगाल के गवर्नर हैं, एक ही बात कही थी कि उन आपद्ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को अगर हम कुछ क्रय-शक्ति दे दें तो कोई मरने नहीं पाएगा। और वही हमारा मूल मंत्र था 1967 में सफलता हासिल करने का। मैंने मनी राज्य सरकारों से कहा कि कठिन श्रम की योजना, सहज श्रम

योजना और खाने पीने के लिए कर्ज देने की जरूरत पड़ी तो वह भी कांजम्यान लाने दें। हमारी कुछ सामाजिक परंपराएं हैं, बंधन हैं। कुछ लोग कठिन श्रम योजना नहीं कर सकते हैं इसलिए नहीं कि उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है, बल्कि समाजी बनावट ऐसी है कि अगर वह ऐसा करें तो समाज में उनके साथ उपहास किया जाएगा। उनके लिए सहज श्रम योजना आवश्यक होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन दोनों तरह के कामों का नहीं कर सकेंगे। उनको भी कुछ क्रय-शक्ति देना आवश्यक हो जाता है। तो वहाँ कांजम्यान लाने देकर वह शक्ति दे सकते हैं। अगर क्रय-शक्ति आ गई तो दावे के साथ कह सकता हूँ हमारे मुल्क में कोई भूख से मर नहीं सकेगा और इस काम को इस साल शुरू किया गया है। मैंने तो अभी हाल में इसकी जिम्मेवारी ली है। परिस्थिति पहले से बिगड़ी हुई थी।

उपसभापति जी, यह भी मालूम होना चाहिए कि जब मैंने इस मंत्रालय को छोड़ा था तब 90 लाख टन के रिजर्व अनाज का छोड़ कर आधा था और उसी अनाज से 3 साल की लगभग अपूर्वाष्ट में जो समस्या पैदा हुई उसका मुकाबला हम कर सके हैं। तो ये तीनों योजनाएं चल रही हैं। जहाँ जहाँ बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र हैं या सूखे से ग्रस्त क्षेत्र हैं या अभावग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ लोगों को राहत पहुँचाई गई है जहाँ बरसात की वजह से पानी की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो गई, जैसे उत्तर बंगाल में या उत्तर बिहार में कोई भी कठिन श्रम योजना लगाना संभव नहीं था, तो उस वक्त मुफ्त में लोगों को खाना दिया गया। जो खाने को उस किचन में आकर नहीं खा सकते थे, ऐसा भी प्रबंध किया गया, कि सस्ते दाम में रीठियां दी जाएं जो फिले जाकर के परिवार के साथ खा सकें।

यह बात स्मरण रखनी है उपसभापति जी और माननीय सदस्यों से मैं कहूँगा यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि हिन्दुस्तान गरीब

दंश हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम भी विकसित देश हो जाएं। हम विकासोन्मुख हैं। यह भी कहते हुए हमें संकोच नहीं होना चाहिए कि सामान्य परिस्थिति में भी देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको दौनों शान्ति की तृप्ति नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में परेशानी उनको बहुत रहती है और जब यह प्राकृतिक प्रकाप हो जाता है तो उनकी परेशानी और भी बढ़ जाती है, उनके कष्ट और भी बढ़ जाते हैं, उनकी डिस्ट्रेस और भी बढ़ जाती है—इससे इन्कार कौन कर सकता है? लेकिन जब ऐसा नाजुक समय होता है तो अपनी कठिनाइयों का अतिरंजन कर देने से कठिनाइयाँ कम तो नहीं हो पाती हैं। कठिनाइयों के अतिरंजन से हम लोगों की कठिनाई का बढ़ा देते हैं। यह स्मरण रखना चाहिए, खाद्य का मामला बहुत नाजुक है। हम अभाव-अभाव कहने लगे तो अभाव हो सकता है। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहूँगा इस नाजुक मामले का विगड़ने नहीं देना चाहिए।

यह फिर अपने आप का धन्यवाद देना होगा उपसभापति जी, जब मैंने यह जिम्मेवारी ली तबमाम मुल्क में एक विश्वास पैदा हो गया है, मुल्क में एक विश्वास आया है और दामों में गिरावट आई है और उससे बढ़कर यह बात हुई है, जब किसी से बातचीत करता हूँ, चाहे बम्बई के, कलकत्ता के, दिल्ली के लोग हों, जिस तबके के लोग हों, कहते हैं कि चीजें मिलने लगी हैं। जहाँ ऐसा हो गया था कि चीजें मिलती नहीं थीं, दाम देने पर भी, अब वह मिलने लग गई है—चाहे वह चीनी का प्रश्न हो, डालडा का प्रश्न हो, गेहूँ का प्रश्न हो, चावल का प्रश्न हो, देहात के क्षेत्र में भी शहर के क्षेत्र में भी। जिस सूबे से हमने मालूम किया हर सूबे को उतना अन्न देने का प्रयत्न किया जिससे वहाँ की परिस्थिति का मुकाबला किया जा सका।

श्री गृणानन्द ठाकुर : बिहार का कहां मिला ?

श्री जगजीवन राम : एक बात जरूर है कि राज्य सरकारें इतनी मांग कर देती हैं जिस मांग की आवश्यकता नहीं होती।

हमारा अनुभव पिछली दफा का है और इस दफे के अनुभव में भी हम यह समझते हैं कि जितनी आवश्यकता है, उतना हम देते हैं; देश में जो प्राप्त किया गया है और विदेशों से जो मंगाया गया है, उसी में से गज्यों को दिया जाना है। निरंन घोष ने कहा कि विदेश से अनाज मंगाने की बात को चुप चुप रखना चाहते हो। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें चुप चुप रखने की क्या बात है। आप क्यों समझ लेते हैं कि आपकी जो काम करने की शैली है, वही हमारी भी शैली है? वह हमारी शैली नहीं है।

SHRI NIREN GHOSH: You give us the figures and also the amount.

श्री जगजीवन राम : मैं फिगर्स नहीं दूँगा। अगर आप हमारे पास आरोगे तो मैं बतला दूँगा। लेकिन यह कहना कि हम अमेरिका से चुप चुप करके अनाज ले रहे हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्यों चुप चुप करके लेंगे? अगर हमें देशवासियों को खिलाना है और उसके लिए बाहर से अनाज मंगाने की आवश्यकता है, तो हम इन्के की चोट पर कहते हैं कि हम अनाज मंगाएंगे और चुप चुप कर नहीं मंगाएंगे और जहाँ से मिलेगा वहाँ से मंगाएंगे। जो लोग अमेरिका के गेहूँ को अर्थात् सपभक्त हैं वे खाना छोड़ दें तो मुझे अफसोस नहीं है। अगर वे अमेरिका के खाद्यान्न को अपवित्र और अस्पृश्य समझते हैं तो...

श्री महावीर लक्ष्मी : अमेरिका का गेहूँ तो लाल होता है।

SHRI NIREN GHOSH : You are contradicting. I said, from the multi-national corporations you are going to purchase.

श्री जगजीवन राम : मल्टी नेशनल कार्पोरेशन से भी लेंगे और वाइलडरल इन्तजाम करके भी लेंगे और जहाँ पर भी देखेंगे कि सहूलियत के साथ मिल रहा है बिना शर्त के, वहाँ से हम लेने का प्रयत्न कर रहे हैं।

SHRI NIREN GHOSH : Give us the entire picture.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is giving you.

श्री जगजीवन राम : इसलिए बाहर भे मंगाकर भी आज जो हमारी वितरण की शैली बन गई है, जितना हम लोगों को वितरण कर रहे हैं, उसको चलाना चाहते हैं ।

खुशी की बात तो यह हुई है कि पिछले महीने जो वर्षा हुई है, उससे किसानों के भीतर एक नया विश्वास आया है और एक नया भरोसा आया है । मैं बतला देना चाहता हूँ कि इससे सरकार के जो राहत के काम चल रहे थे, उसमें भी सुविधा आ गई है । सुविधा का अर्थ यह है कि जब किसान कार्तिक की फसल बोता है, अगर उसके पास अपने साधन न हों, तब भी किसान का हृदय ऐसा होता है कि वह अपने खेत को आबाद करने के लिए अपने जेवर बन्धक रखकर उस काम को कर लेता है । जो उसके काम करने वाले श्रमिक होते हैं उनकी भी वह चिन्ता कर लेता है । तो यह स्थिति ऐसी पैदा हुई है कि हिन्दुस्तान के प्रायः सभी राज्यों में संतोषजनक वर्षा होने की वजह से रबी की फसल की अच्छी उम्मीद बन गई है ।

उप-सभापति जी, आपका मालूम है कि जब किसान को यह मालूम हो जाता है कि अगली फसल की उम्मीद अच्छी है, तो उसके घर में जो कुछ जरूरत से ज्यादा अनाज होता है वह बचने के लिए निकाल देता है । खासकर के गेहूँ के मामले में तो इस समय अगर एक महीने की भी देरी की तो गेहूँ के बरबाद हो जाने का भय रहता है । लेकिन यह बात हमारे यहां के बहुत लोगों को मालूम नहीं है पर किसान यह बात जानता है इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों को अपना गेहूँ निकालना ही पड़ेगा । जो बड़े-बड़े किसान हैं उनके पास गल्ला है । मुझे कुछ बड़े किसानों से इस बारे में सूचना मिली है और उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ । किसी किसी क्षेत्र के किसानों को भरोसा और विश्वास हमारे में है और उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा है कि फलां, फलां केन्द्र हैं और वहां के किसानों के पास गेहूँ है । मैंने राज्य सरकारों के पास खत लिखा है

कि बड़े बड़े किसानों से अनाज निकालने का प्रयत्न होना चाहिए । मैंने यह भी कहा है और मैं इस बात को फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष का किसान दशभक्त है । भारतवर्ष का किसान निरक्षर हो सकता है, लेकिन बेअकल नहीं है । उसके पास साधारण बुद्धि होती है और मैंने यह भी कहा था कि किसान चन्द रुपयों के लिए समाज के लोगों को परेशान करना उचित नहीं समझता है । मैं मानता हूँ कि इसका कुछ असर हुआ है । राज्य सरकारों को मैंने यह भी कहा था कि अनुरोध करने से, निवेदन करने से अगर यह गल्ला नहीं निकलता तो कानून की जितनी शक्ति हमारे पास है सब का उपयोग करके इसका गल्ला निकालना चाहिए, डिपेंस आफ इंडिया ऐक्ट का इस्तेमाल करके, एग्जिश्यल कमांडिटीज ऐक्ट का इस्तेमाल करके और आवश्यकता पड़े तो मीसा का इस्तेमाल करके । मुझे यह कहते हुए मन्ताप है कि इन प्रयत्नों के फलस्वरूप करीब एक लाख टन गल्ला बाहर निकाला जा चुका है और हमारे ये प्रयत्न जारी हैं । हमें उम्मीद है कि बहुत ज्यादा कानून का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, किसान स्वच्छा से अपनी आवश्यकता से अधिक जो गल्ला उनके पास है उसका निकाल देंगे ।

चेत्र की फसल मार्च-अप्रैल तक कटंगी, मई तक बाजार आ जायगी । जिस मिकदार में राज्य सरकारों का हम सहायता कर रहे हैं—वह फिर देने की आवश्यकता में नहीं सम्भक्त, लोगों को मालूम है—उसी हिसाब से अभी चलाना चाहते हैं । जहां-जहां अगहनी की कटनी हो रही है, धान आ रहा है, वहां राहत कुछ अधिक पहुंच रही है । इस समस्या का मुस्तकिल समाधान यही हो सकता है कि प्रकृति का कठिन से कठिन प्रकोप हो जाय, अनावृष्टि हो जाय, वंसी हालत में भी हम अपने देश में उतना अनाज पैदा कर लें जितना अपने देशवासियों का खिलाने के लिए आवश्यक है । गेरा प्रयत्न इसी दिशा में होगा । पहले दिन, उपसभापति जी, जब मैंने इस मंत्रालय का भार ग्रहण किया तो अपने अफसरों से यही कहा था कि भारत के लिए वह शुभ दिन होगा जिस दिन केन्द्र में खाद्य विभाग नहीं रहेगा ।

आज हम करते क्या हैं खाद्य विभाग से ? कुछ राज्य सरकारों को तकाजा करके कहते हैं कि प्रोक्वोरमेंट कर लो, वसूली कर लो, अनाज का भंडार बना लो, जो तुम्हारी आवश्यकता से अधिक है वह केंद्र के भंडार में दे दो। यह सब करने के बाद भी जब साल भर खिलाने के लिए कम पड़ता है तब प्रयत्न करते हैं कि विदेश से मंगा कर अपना भंडार बना लें। केंद्र में खाद्य विभाग की आवश्यकता इसलिए है कि जितना हम खाते हैं उतना पैदा नहीं कर पाते हैं; उतना पैदा कर लेते तो उसकी जरूरत नहीं रह जाती। खाद्य पर या वितरण पर नियंत्रण की आवश्यकता तभी होती है जब हमारे यहाँ अभाव की स्थिति होती है। जब अभाव नहीं रहता है तो मैंने इसका अनुभव किया 1969 में कि दिल्ली में खाद्य का नियंत्रित वितरण टूट रहा है, लोग ही वहाँ नहीं जाते। जब बाजार में खुल्लाम मिलेगा तो कोई फेयर प्राइस शाप पर और राशन की शाप पर नहीं जाएगा; वहाँ जाएगा जहाँ दान्तीन किस्मों की चीज को देख कर चुन कर ले सके, चाहे चार पैसे ज्यादा देने पड़े। यही मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन हमको हर स्थिति के लिए प्रबंध करना पड़ेगा।

मैंने यह तय किया है कि सिंचाई सम्बन्धी उन योजनाओं को पूरा करने का यत्न किया जाए जो जल्दी फल दे सकती हैं।

SHRI MAHAVIR TYAGI : Congratulations. This is the only solution.

श्री जगजीवन राम : जहाँ पानी के बंटवारे के मामले को लेकर राज्य सरकारों में मतभेद है मैं प्रयत्न करूँगा कि उसका जल्दी से जल्दी सुलझा दिया जाए। छोटी और मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं को भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, यह भी हमारा प्रयत्न होगा। यह बात सबको मालूम है कि आज हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन इस तथ्य को भी भुलाया नहीं जा सकता कि हमारा आर्थिक तंत्र बहुत अंश में कृषि पर निर्भर है। जिस साल फसल अच्छी है जाती है देश के अर्थशास्त्री कहने लगते हैं कि अब देश की अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है; जिस साल कृषि की उपज कम हो जाती है अर्थशास्त्री

कहने लगते हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था ढीली हो रही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी कई-एक दशक तक हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर निर्भर करेगी। कृषि आज भी हमारे राष्ट्र की आय का एक बहुत बड़ा अंश देता है।

आधे से थोड़ा ही कम। कृषि ऐसा उद्योग है हमारे देश का जिससे आज भी, इस हालत में भी 80-82 प्रतिशत लोगों का निर्वाहन हो रहा है इन्फ्लायमेंट के हिसाब से। इसलिए कृषि को जितना तेजी से हम सशक्त बना सकें और सक्षम बना सकें उतना ही देश को हर दृष्टि से लाभदायक होगा।

मैंने मित्र नीरेन घोष ने कहा कि डिफेंस के बजट को कम कर दो। मैं उनकी सलाह को मान लेता अगर किसी सूचना के आधार पर ऐसा उन्होंने कहा होता। सूचना का आधार यह कि हमारे उत्तर पूर्व की सीमा पर, मैंने चीन का जिक्र किया था, चीन है। हमारे प्रयत्न करते रहने पर भी, हमारे विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री के मित्रता का हाथ बढ़ाने के बावजूद भी चीन का हाथ उस हाथ को पकड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ा है। वैसे हालत में कोई भी देशभक्त जो मातृभूमि की सरहद की सुरक्षा चाहता है, डिफेंस के बजट में कमी करने की इस वक्त सलाह नहीं दे सकता। इसलिए मंत्री मजबूरी है। लेकिन कृषि और सिंचाई के लिए सारे मुल्क की आर्थिक अवस्था को मद्दे नजर रखते हुए जितना अधिक से अधिक हम लगा सकते हैं, लगाने का यत्न करेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि वही एक रास्ता है जिससे खाद्यान्न के मामले में हम देश को स्वावलम्बी बना सकते हैं सिर्फ खाद्यान्न ही नहीं, जब कृषि के मामले में मैं सोचता हूँ तो आपको मालूम है, उप-सभापति जी, कि हमारी कृषि से न सिर्फ लोगों को खाने का मिलता है, हमारे देश के कई बड़े-बड़े उद्योग कृषि के ऊपर निर्भर हैं जिनमें राष्ट्रीय सम्पत्ति से अभिवृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ बहुत से परिवारों का निर्वाहन होता है उन उद्योगों में काम धन्धा करके। उदाहरण देना है तो वे तीन दे दूँ। टैक्सटाइल है, कपड़े के कारखाने हैं, बड़े

रुई के ऊपर आधारित हैं, कपास के ऊपर आधारित हैं। जूट के कारखाने हैं, जिससे हम बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा अर्जन करते हैं, वह भी कृषि के उत्पादन पर निर्भर है। चीनी के कारखाने ले लीजिए। चीनी का उद्योग चलता है तो वह भी कृषि से उत्पन्न होता है। मैंने वे-तीन बातों का नमूना पेश किया। सांचा जाए तो बहुत सी चीजें हैं। वनस्पति है, वह भी कृषि के ऊपर निर्भर करता है। तो खाद्यान्न और दूध के कई बड़े उद्योगों को कच्चा माल देना हमारी कृषि की उपज के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कृषि को प्रोत्साहित करना पहला काम है।

छांटें किसानों की बात हुई। बिहार में बाढ़ आई तो बिहार में ही नहीं आई, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, उत्तर बिहार में, उत्तर बंगाल में भी आई। मैं उस वक्त कृषि मंत्री नहीं था, लेकिन मैंने तीनों जगह हवाई-जहाज से देखा, कहीं कहीं उत्तरा भी और इस साल की बाढ़ की स्थिति इसलिए भयंकर थी कि पहले जब बाढ़ आती थी तो वे तीन दिन में पानी निकल जाता था, लेकिन इस साल पानी का उन इलाकों से इतनी मोहल्लत है गई थी कि वह जानों का नाम ही नहीं लेता था। इसका नतीजा यह हुआ कि जो धान की फसल खड़ी हुई थी वह गल गई। किसान के घर में जो कुछ था वह बह गया। अजीब हालत प्रकृत की है। पता नहीं कभी प्रकृत भी अकल से काम लेना सीखेगी या नहीं। लेकिन यह तो हुआ जहां पानी था। जहां वृष्टि थी वहां बरसता गया, जहां पानी नहीं था, जैसा बिहार का दक्षिणी भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में सब वृष्टि के अभाव में परेशान थे, ऐसा लगने लगा था कि थोड़ी देर और पानी नहीं पड़ता तो लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा चाहे सौराष्ट्र हो, कुछ हो, राजस्थान हो और बिहार का दक्षिणी हिस्सा है या मध्य प्रदेश हो वहां पानी नहीं बरसा। जो असम कुछ चावल केन्द्र का देता था उसे आज केन्द्र से खाद्यान्न लेने की आवश्यकता हुई केन्द्र ने उनको दिया। असम की एक और स्थिति है और कुछ पश्चिमी बंगाल की भी।

उसके बारे में कुछ इशारा कर देना चाहता हूँ। बंगला देश का निर्माण हुआ। भारत का उसमें योगदान रहा। लेकिन कई वर्षों से पाकिस्तान का निर्माण होने के बाद से उस समय के पूर्वी बंगाल के साथ जिस तरह व्यवहार होता रहा वह इतिहास की बात है। पाकिस्तान ने वहाँ से जाने से पहले जिस तरह से बंगला देश की सारी आर्थिक अवस्था को नष्ट-भूष्ट कर गया था वह भी इतिहास की बात है। वहाँ से परेशान हुंकर भी कुछ लोग आए हैं पश्चिमी बंगाल में और असम में भी। इतना इंगित कर देना मैंने आवश्यक समझा। जो आते हैं कुरी हालत में आते हैं।

मैं कह रहा था कि पश्चिमी बंगाल में बाढ़ की स्थिति रही है। हमने यह भी देखा इस साल लोग परेशान रहे हैं। अगर समय रहते हम रबी की बुवाई का अच्छा इन्तजाम कर लें तो आने वाली रबी की फसल तक हमको राहत मिल जाएगी। इसका देखते हुए हमने एक अफसर का तैनात किया है। जो खाद का, बीज का और क्रीडेट का यानी इन सब चीजों का संभालेगा। अफसर का यह भी हिदायत दी गई है कि वह इससे ही सन्तोष न कर ले कि फलों राज्य का इतनी खाद प्लांट कर दी है, फलों राज्य का इतने बीज प्लांट कर दिए हैं वॉलक यह भी टैलकॉन करके सूचना लेनी चाहिए कि हर राज्य की सरकार के पास खाद पहुंच गई या नहीं, बीज पहुंच गए या नहीं। डिस्ट्रिक्ट में चले गए या नहीं और डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉकों में गए या नहीं। यह सब मैंने कहा था। बिहार के मामले में भी मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने खाद और बीज ब्लॉक में पहुंचा दिए हैं। वहाँ के रेवेन्यू गिनिस्टर आए थे उन्होंने आते ही यह खबर दी है कि यह सब चीजें ब्लॉक तक पहुंच गई हैं। यह मैंने इन्तजाम किया है।

यह भी खुशी की बात है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री दोनों ने कहा है कि इस दुफा बादल ने अकल से काम लिया है। राजस्थान में जहां रबी की फसल होनी है वहाँ अच्छा पानी पड़ गया। गुजरात में, सौराष्ट्र में, कच्छ, बनासकांठा में भी अच्छा पानी पड़ गया। छत्तीसगढ़ में जितना पानी होना चाहिए था उतना

पानी नहीं पड़ा। असम और बंगाल में खी का प्रोश्राम बन गया है। कितनी खाद चाहिए, कितने बीज चाहिए और कितना क्रीडट चाहिए यह सब वहाँ से डिमांड मंगा कर उपलब्ध करा दी है।

जो लोग आज तक यह समझते थे कि असम और बंगाल में सिर्फ धान होता है वहाँ आज अच्छे किस्म के और ज्यादा गेहूँ पैदा होने लगा है जितना जालंधर और लुधियाना में होता है। यह हमने प्रयत्न किया है। यही मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि खाद धीज और आवश्यक क्रीडट सभी सरकारों को उपलब्ध करा दिया गया है। जिन्होंने कुछ और क्रीडट मांगा, ऋण मांगा उसके लिए भी हमने बैंक से लिखा-पट्टी की प्रवन्ध कराने के लिए। हम यह चाहते हैं कि खी की फसल की बुवाई समय पर हो जाए। कुछ किस्म के गेहूँ हैं जिनको नवम्बर में बो दिया जाता है, कुछ किस्म ऐसी हैं जिनको दिसम्बर के अंत तक चलाया जा सकता है और कुछ किस्म ऐसी हैं जिनको जनवरी के पूर्वार्ध में बो जाया जा सकता है। खी की बुवाई अच्छी होगी इस पर पूरा भरोसा है। मैंने कहा कि हमने कभी खाद्य के मामले में राजनीति की बात नहीं साँची है। पिछली दफा जब मैं 5 p.m. खाद्य मंत्री था तो बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार थी। अगर नीरेन बाबू, उस वक्त के जो मुख्य मंत्री थे उनसे पूछेंगे तो उनका मालूम होगा कि हमारी तरफ से सहायता और सहयोग में कोई भी शिकायत की गंजायश नहीं थी।

SHRI NIREN GHOSH : This much I must say that some Ministers came here to offer dharna for food.

श्री जगजीवन राम : एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। मैं यह कहूँ कि मैं डिस-क्रिमिनेशन करूँगा और डिस्क्रिमिनेट करना भी चाहूँ तो मैं वह कर नहीं सकता क्योंकि अगर कोई कहे कि किसी दुकान पर कांग्रेस वालों का अनाज नहीं मिलेगा तो यह नहीं हो सकता। इसलिए पॉलीटिकल डिस्क्रिमिनेशन की बात करना, खासतौर से खाद्य के मामले में, मैं समझता हूँ कि जो लोग इस

प्रकार की बात करते हैं, वे अपनी अक्ल को बाहर छोड़कर आते हैं। यह हाँ ही नहीं सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमको ऐसे मामलों में राजनीतिक से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। हो सकता है कि जो लोग इस प्रकार की बातें कहते हैं उनका और उनकी पार्टी का इसमें कुछ शक्ति मिल सकती है, लेकिन यह क्षणिक शक्ति होगी, वह टिकाऊ शक्ति नहीं होगी।

अभी श्री नीरेन बाबू ने भूख से मरने वालों के आंकड़े दिये हैं और बारबार उनका दाहराया है। मैं कहता हूँ कि आप 25 हजार कंसज में डार्ड साँ लोगों के नाम लेकर कह दीजिए कि फलों फलों गाँव में अनाज के अभाव से लोग मरे हैं तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि उस वक्त उस गाँव के इर्दगिर्द अनाज था या नहीं था। अगर अनाज था तो अनाज के बिना किस प्रकार लोग मर गये। लेकिन आज स्थिति यह है कि हमारे देश के पट्टी-लखे लोगों के मन में यह बात घर कर गई कि अनाज ही पहले आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि पहली आवश्यक चीज व्यक्ति की परबीजंग पावर है। मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारा गरीब देश है। बहुत नारामल टाइम में, साधारण स्थिति में भी इन बातों से लोगों का तबलीफ खूबी है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। हम लोग उसी काम में लगे हुए हैं कि हमारे देश के लोगों का जीवन स्तर ऊँचा हो। हमारा किसी दल से या किसी पार्टी से राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन इसमें कोई मतभेद की गंजायश नहीं है कि हमें भारत को समृद्धशाली और शक्तिशाली देश बनाना है।

श्री महावीर त्यागी : इसमें यह तमाम पार्टियों आपका साथ देंगी।

श्री जगजीवन राम : हम इसका बिलकुल स्वागत करते हैं। श्री नीरेन घोष ने पीडित जवाहर लाल नेहरू का जिक्र किया और साथ ही यह भी कहा कि वे आपके नेता थे, हमारे नेता नहीं थे। नीरेन बाबू, भारत में आपके नेता नहीं मिल सकता है।

SHRI NJREN GHOSH : I will not go and search for leaders inside the Congress. Never, you can rest assured on this.

SHRI JAGJIVAN RAM: I am just interpreting what you have said and it fits on you.

SHRI NIREN GHOSH : You seek your ideological inspiration from America and England. Let me remind you of that also.

श्री जगजीवन राम : मैं आपकी बातों की व्याख्या कर रहा था, और कुछ नहीं कह रहा था। भारत की एक गरिमा रही है और हम इस प्रयत्न में लगे हुए हैं कि वह दिन शीघ्र आ सके जब हम सिर उठाकर कह सकें कि आज हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके खाना न मिला हो या जो रात को खाना खाकर नहीं सोया है, किसी का कपड़े का अभाव नहीं है, मकान का अभाव नहीं है, किसी का शिक्षा का अभाव नहीं है। लेकिन साथ ही हमें यह कहने में भी संकोच नहीं है कि हम इसका अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। आज भी देश में बहुत लोग हैं—जिनका समय पर भरपेट खाना नहीं मिलता है, जिनका जरूरत भर कपड़ा नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि यह स्थिति जल्दी से जल्दी दूर हो। उपसभापति महोदय, वहां पर कहा गया था कि इस मामले में सभी लोगों की राय होनी चाहिए। मैंने ऐसा विचार है कि हम एक अखिल भारतीय स्तर पर एक फूड एंडवाइजरी काउंसिल बनायें जिसमें माहिर लोगों का रखा जाय फिलिस्मनों का रखा जाय और सभी की सलाह और राय इसमें ली जाय। मैं समझता हूँ कि खाद्यान्न समस्या का छिपाने की बात नहीं है। हमारे देश की जो स्थिति है, हमारे देश में जो संकट है, उसमें हम आप सब का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम मिलकर इस संकट को जितना

हल्का बना सकें, हल्का करें। वाणी से संकट हल्का बनाया जा सकता है और वाणी से ही संकट को गम्भीर भी बनाया जा सकता है।

मैंने कहीं कहा था, यदि नहीं कहा, कि हमारे देश में कम से कम 12 करोड़ परिवार होंगे; अगर हम अभाव की स्थिति पैदा करते रहें और ये 12 करोड़ गृहीणियों और कुछ नहीं करें, दस-दस किलो अपने पास रख लें, तो 12 लाख टन हो जाएगा। 12 लाख टन अगर इन्फ्लैटिव लाइज हो जाएगा तो अभाव की स्थिति पैदा हो सकती है इसलिए मैंने गृहीणियों से अनुबंध किया था कि खरीद कर के अपने घर में अन्न भण्डार नहीं बनाओ उससे परेशानी बढ़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि खाद्य का प्रश्न एक बहुत नाजूक प्रश्न है, बहुत डीलिकेट है, इसलिए कोई काम या किसी तरह का कहना ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अभाव की आवांहा को और भी गम्भीर बना दें। तो मैंने इस बहस का स्वागत किया है, आप लोगों ने जो राय दी है कृपि मैं सुधार करने की दृष्टि से

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) : एक बार फिर विश्वास दिलाता हूँ, विरोधी दल पूरी तरह से आपके साथ इस मामले में सहयोग करेगा।

श्री जगजीवन राम : आप तो हमारे साथ ही बराबर रहें, उस तरफ बैठ गए तो क्या हुआ ? भाई, आप उस तरफ भी बैठ गए तो रक्त आपके वदन में बही तो है। मैं फिर दूहराउंगा उपसभापति जी, कि खाद्य के प्रश्न को राजनीति का प्रश्न बनाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। खाद्य के संकट की वजह से लोगों को जो परेशानी होती है उस परेशानी को लेकर सत्तारूढ़ सरकार को मारने का प्रयत्न भी नहीं होना

चाहिए, हालांकि उस मार में कंडा बात नहीं रहती है . . .

श्री महावीर त्यागी : आपकी प्राइम मिनिस्टर बधाई का योग्य है इसलिए कि आपको उन्होंने यह महकमा दिया है। यह वाकई बड़ा अच्छा काम किया है वरना खतरे में थे हम सब।

श्री जगजीवन राम : मंरा भी यह सँभाग्य है त्यागी जी, देश में कठिन से कठिन काम जब मँने लिया है तो आप लोगों का सहयोग चाहा

है और इस बार भी इन जिम्मेदारियों को लिया तो इसी भरसे पर लिया कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि देश की जनता चाहती है कि मैं उस जिम्मेवारी को लूँ। सब का सहयोग मिला है। मुझे भरोसा है कि सब के सहयोग से देश को इस संकट की घड़ी से हम निकाल सकेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11.00 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at eight minutes past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 27th November, 1974.